twitter.com/divyadelhi facebook.com/divyadelhi infodivyadelhi@gmail.com Editor: Rajesh Chauhan

RNI No. DELHI/2013/54397

दिव्य दिल्ली

divyadelhi.com | गुरूवार, 10 जुलाई, 2025 | वर्ष: 12, अंक: 234, पृष्ठ: 08 | ₹ 05/- | दिल्ली से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र

मोदी को मिला नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान

प्रधानमंत्री मोदी ने नामीबिया की संसद के संयुक्त सत्र को किया संबोधित

नई दिल्ली/एजेंसी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बुधवार को नामीबिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्विस्शिया मिराबिलिस से नवाजा गया। यह प्रधानमंत्री मोदी को मिला 27वां अंतरराष्ट्रीय और उनकी वर्तमान में जारी पांच देशों की यात्रा के दौरान चौथा सम्मान है। प्रधानमंत्री मोदी की नामीबिया की आधिकारिक यात्रा के दौरान वहां की राष्ट्रपति डॉ. नेटुम्बो नंदी-नदैतवाह ने आज सम्मान समारोह में प्रधानमंत्री को इससे नवाजा। सम्मान ग्रहण करने के बाद उन्होंने सम्मान को दोनों देशों को समर्पित किया और साथ मिलकर निरंतर प्रगति और विकास के लिए काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह उनके लिए अत्यंत गर्व और सम्मान की बात है और इसे वे 140 करोड़ भारतीयों की ओर से स्वीकार कर रहे हैं। संबंधों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने नामीबिया के दुनिया के सबसे बड़े हीरा उत्पादन देश और भारत के सबसे बड़े पॉलिशिंग उद्योग देश होने का संदर्भ दिया और भविष्य की साझेदारी में विश्वास को दोहराया। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी साझेदारी भी इन हीरों की तरह चमकेगी। नामीबिया की आजादी के कुछ सालों के बाद 1995 में इस सम्मान की शुरूआत की गई थी। इसका उद्देश्य विशिष्ट सेवा और

भारत-नामीबिया एक-दूसरे के साथ खड़े रहे हैं: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने नामीबिया में भारतीय डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई के लॉन्च की घोषणा करते हुए कहा कि यह सेवा जल्द ही शुरू होगी, जिससे पैसे का लेनदेन टांगी उनेने (बहुत धन्यवाद) बोलने से भी तेज हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत नामीबिया को भाभाट्रॉन रेडियोथेरेपी मशीन देने जा रहा है, जिससे कैंसर के इलाज में मदद मिलेगी। उन्होंने जनऔषधि योजना से दिया, जिससे सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

उन्होंने सम्मान को भारत और नामीबिया की चिरस्थायी मैत्री का साक्षी बताया। उन्होंने कहा कि एक सच्चे मित्र की पहचान कठिन समय में ही होती है। भारत और नामीबिया अपने स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही एक-दूसरे के साथ खड़े रहे हैं।

नेतृत्व का सम्मान देना है। इसका नाम वेल्विस्शिया मिराबिलिस के नाम पर रखा गया है। यह नामीबिया का एक प्राचीन रेगिस्तानी पौधा है। नामीबियाई लोगों के लचीलेपन, दीर्घायु और स्थायी भावना का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने सम्मान से जुड़े प्रतीकात्मक अर्थ का उल्लेख किया और कहा कि वेल्विस्शिया पौधे को नामीबियाई लोगों के संघर्ष, साहस और संस्कृति का प्रतीक माना जाता है और यह समय के बीतने के साक्षी परिवार के बुजुर्गों के समान है। मैत्री और सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता जताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और नामीबिया के बीच ऐतिहासिक मित्रता पर जोर दिया। उन्होंने सम्मान को भारत और नामीबिया की चिरस्थायी मैत्री का साक्षी बताया। उन्होंने कहा कि एक सच्चे मित्र की पहचान कठिन समय में ही होती है। भारत और नामीबिया अपने स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही एक-दूसरे के साथ खड़े रहे हैं।

संस्कृति और गरिमा के साथ पाई जा सकती है सफलता: मोदी

नई दिल्ली/एजेंसी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नामीबिया की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए भारत के संविधान को लोकतंत्र की असली ताकत बताया। साथ ही संदेश दिया कि अपनी संस्कृति और गरिमा के साथ सफलता पाई जा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि भारत-नामीबिया द्विपक्षीय व्यापार 80 करोड़ डॉलर पार कर चुका है। उन्होंने इसे क्रिकेट मैच की शुरूआत बताया और कहा कि अब तेजी से स्कोरिंग होगी। भारत द्वारा स्थापित उद्यमिता विकास केंद्र नामीबियाई युवाओं के लिए नवाचार और सहयोग का केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि भारत न केवल अपने विकास की दिशा तय कर रहा है, बल्कि ग्लोबल साउथ के सपनों को भी दिशा दे रहा है। भारत का संदेश है, अपनी संस्कृति और गरिमा के साथ सफलता पाई जा सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की अफ्रीका में विकास भागीदारी 12 अरब डॉलर से अधिक की है, लेकिन इसकी असली ताकत साझा विकास और साझा उद्देश्य में निहित है। प्रधानमंत्री ने नामीबिया के स्वतंत्रता संग्राम में भारत की भूमिका को याद करते हुए बताया कि भारत ने स्वात अफ्रीका के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में तब उठाया, जब वह स्वयं स्वतंत्र नहीं था। भारत ने आंदोलन का समर्थन किया और नामीबिया में भारत की पहली विदेश-स्थित राजनयिक इकाई खोली।

स्टारलिंक को मिली भारत में इंटरनेट सैटेलाइट संचालन की मंजूरी

नई दिल्ली/एजेंसी

ऐलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू करने की सभी मंजूरियां मिल गई हैं। भारत के अंतरिक्ष नियामक इन-स्पेस ने उद्योगपति ऐलन मस्क की स्टारलिंक को देश में उपग्रह-आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने का लाइसेंस दे दिया है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (इन-स्पेस) ने अपनी वेबसाइट पर दी गई जानकारी में बताया कि उसने स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशंस को भारत में स्टारलिंक जेन1 कॉन्स्टेलेशन क्षमता के प्रावधान को सक्षम करने की अपनी मंजूरी दे दी है। स्टारलिंक तीसरी कंपनी है, जिसे भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस ऑपरेट करने का लाइसेंस मिला है। इससे पहले वनवेब और रिलायंस जियो को मंजूरी मिली थी। इन-स्पेस ने बताया कि स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशंस को भारत में स्टारलिंक जेन1 कॉन्स्टेलेशन क्षमता के प्रावधान को सक्षम करने के लिए दी गई ये मंजूरी पांच साल की अवधि के लिए वैध है। स्टारलिंक 2022 से ही वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने के लिए भारतीय बाजार पर अपनी नजर गड़ाए हुए थी।

एनआईए ने तहव्वुर के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट

नई दिल्ली/एजेंसी

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बुधवार को तहव्वुर राणा के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। स्पेशल जज चंदर जीत सिंह ने 2008 में 26 नवंबर को मुंबई में हुए आतंकी हमलों के साजिशकर्ता तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत 13 अगस्त तक बढ़ा दी है। आज तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उसे वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश किया गया। तहव्वुर को अमेरिका के शिकागो में अक्टूबर, 2009 में अमेरिकी एजेंसी एफबीआई ने गिरफ्तार किया था। राणा को प्रत्यर्पण करके 10 अप्रैल को स्पेशल विमान के जरिये अमेरिका से भारत लाया गया था। तभी एनआईए ने 10 अप्रैल की शाम को दिल्ली के पालम वायुसेना अड्डे पर उतरते ही राणा को गिरफ्तार किया था।

दिल्ली-एनसीआर में झमाझम बारिश

नई दिल्ली/एजेंसी

राजधानी दिल्ली में बुधवार शाम को हुई झमाझम बारिश ने उमस भरी गर्मी से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत दी। दिनभर की चिपचिपी गर्मी और भारी उमस के बाद अचानक बदले मौसम ने तापमान में भी अच्छी गिरावट ला दी। दिल्ली के साथ-साथ गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद जैसे एनसीआर के इलाकों में भी तेज हवाओं और हल्की गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। बारिश की वजह से कई इलाकों में ट्रैफिक की रफ्तार थम गई। राजधानी दिल्ली के कश्मीरी गेट के पास आईएसबीटी इलाके में बारिश की वजह से हुए जलभराव से जाम की

स्थिति देखी गई, वहीं कुछ निचले इलाकों में जलभराव से लोगों को परेशानी हो रही है। मौसम विभाग ने पहले ही दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया था। विभाग का अनुमान है कि आने वाले दो दिनों में भी राजधानी में गरज-चमक के साथ बारिश जारी रह सकती है। बादल छाए रहेंगे और गर्मी से राहत की उम्मीद बनी रहेगी। हालांकि, इस बार दिल्ली में मॉनसून ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया है। 1 जून से 9 जुलाई तक की अवधि में यहां सामान्य से 23 फीसदी कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। आसमान में बादल तो कई बार दिखाई देते हैं, लेकिन ज्यादातर समय वे खाली ही लौट जाते हैं।

सेवानिवृत्ति के बाद प्राकृतिक खेती और वेद-अध्ययन करेंगे अमित शाह

अहमदाबाद/एजेंसी

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बुधवार को सहकार संवाद कार्यक्रम के दौरान अपनी सेवानिवृत्ति के बाद की योजनाओं पर बात की। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन से संन्यास लेने के बाद वे प्राकृतिक खेती करेंगे और वेदों, उपनिषदों सहित हिंदू धर्मग्रंथों का गहन अध्ययन करेंगे। अहमदाबाद में आयोजित इस कार्यक्रम में गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सहकारिता क्षेत्र से

जुड़ी महिलाओं और अन्य कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि प्राकृतिक खेती एक वैज्ञानिक पद्धति है, जो न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, बल्कि उत्पादन भी बढ़ाती है। उन्होंने बताया कि वे भी अपने खेतों में इसका प्रयोग करते हैं। इससे उन्हें डेढ़ गुना अधिक उत्पादन प्राप्त हुआ है। शाह ने रासायनिक खेती से होने वाले नुकसान की चर्चा करते हुए कहा कि केमिकलयुक्त अनाज से बीपी, डायबिटीज और थायरॉइड जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। वहीं, प्राकृतिक खेती से शरीर रोगमुक्त होता है और दवाइयों की जरूरत भी कम हो जाती है। उन्होंने बताया कि केचुए प्राकृतिक खाद का काम करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और जल संरक्षण भी होता है।

भारतीय वायु सेना का फाइटर प्लेन जगुआर क्रैश, दो की मौत

जयपुर/बीकानेर/एजेंसी

राजस्थान के चूरू में राजलदेसर थाना क्षेत्र में भारतीय वायु सेना का फाइटर प्लेन जगुआर क्रैश हो गया है। हादसे में दो लोगों की मौत की आशंका है।

चूरू एसपी जय यादव ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि बुधवार दोपहर राजलदेसर थाना क्षेत्र के गांव भाणूदा में वायु सेना का ट्विन सीटर फाइटर प्लेन जगुआर क्रैश हुआ है। इसमें दो लोगों की मौत हुई है। मौके पर राजलदेसर पुलिस को भेजा गया है। मलबे के पास से बुरी तरह क्षत-विक्षत शव के टुकड़े मिले हैं। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई है। मानव अंग सहित प्लेन के टुकड़े भी जगह-जगह बिखर गए हैं।

ग्रामीणों के अनुसार आसमान में तेज आवाज के बाद खेतों में आग की लपटें और धुआं उठता देखा गया। करीब 200 फीट के क्षेत्र में जगह-जगह प्लेन के जलते हुए टुकड़े गिरे हैं। सेना और स्थानीय प्रशासन ने शव के पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कलेक्टर अभिषेक सुराना और स्थानीय पुलिस अधिकारी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। सेना की रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंच रही है। भारतीय सेना से जुड़े सूत्रों के अनुसार हादसे के तुरंत बाद वायु सेना और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि पायलट सुरक्षित है या नहीं। हादसे का कारण तकनीकी खराबी थी या कोई अन्य वजह। घटना की गंभीरता को देखते हुए रक्षा मंत्रालय की ओर से भी जांच के आदेश दिए जा सकते हैं।

गुजरात पुल हादसा: कई वाहन नदी में गिरे, 13 की मौत

वडोदरा/एजेंसी

राज्य में मध्य गुजरात को सौराष्ट्र से जोड़ने वाली महिसागर नदी पर बना पुल के अचानक ढहने से कई वाहन नदी में गिरने 13 लोगों की मौत हो गई है। जबकि आठ लोगों को बचा लिया गया। कोष से मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये और घायलों को पचास-पचास हजार रुपये का मुआवजा देने का ऐलान किया। मुख्यमंत्रीभूपेन्द्र पटेल ने भी राज्य सरकार की ओर से भी मृतकों के परिवारों को चार-चार लाख और घायलों को पचास-पचास हजार रुपये का मुआवजा

देने की घोषणा की है। मध्य गुजरात को सौराष्ट्र से जोड़ने वाली महिसागर नदी पर बना पुल लगभग 45 साल पुराना है। बुधवार सुबह यातायात के दौरान दो ट्रक, दो पिकअप और एक रिक्शा महिसागर नदी में गिर गए। पुल के टूटने और कई वाहनों के गिरने से मौके पर हाहाकर मच गया। घटना की जानकारी होने पर मुजपुर समेत आसपास के गांवों के लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। मुजपुर गांव के ग्रामीण बचाव कार्य के लिए जुट गए और नदी में फंसे व बहते लोगों को कई लोगों को बचाया। इस हादसे में अभी तक नौ लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 8 से ज्यादा लोगों को बचा लिया गया। घटना की जानकारी मिलने पर पादरा पुलिस भी मौके पर पहुंची गई और शवों को निकाला। सुसाइड पॉइंट के रूप में बदनाम इस पुल के ढहने से आणंद, वडोदरा, भरूच और अंकलेश्वर का संपर्क टूट गया है।

कपास उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि मंत्रालय बनाएगा रोडमैप

नई दिल्ली/एजेंसी

कपास उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि मंत्रालय रोड मैप तैयार करेगा। इसके लिए किसानों से सुझाव मांगे गए हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कपास का उत्पादकता अभी काफी कम है और बीटी कॉटन टीएसवी वायरस के कारण उत्पादकता लगातार घटी है। कपास का उत्पादन कम होने से किसान संकट में हैं। मंत्रालय कपास के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। इसके साथ मंत्रालय उत्पादन लागत को घटाने, जलवायु अनुकूल अच्छे बीज विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है। कपास उत्पादक किसानों के प्रतिनिधि, किसान संगठनों के प्रतिनिधि, आईसएआर के जाने-माने सभी वैज्ञानिक, स्वयं डीजी आईसीएआर, कपास उत्पादक राज्यों के कृषि मंत्रीगण, राज्य सरकार के अधिकारीगण, कपास उद्यौग से जुड़े हुए प्रतिनिधि और कृषि विश्वविद्यालयों के लोग भी रहेंगे।

राष्ट्रविरोधी-समाजविरोधी तत्वों को चकनाचूर करके रहेंगे: योगी

आजमगढ़/एजेंसी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ में समाज विरोधी व राष्ट्रविरोधी तत्वों के खिलाफ हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि समाज विरोधी व राष्ट्रविरोधी कार्यवाही में लिप्त तत्वों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में एक जल्लाद को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। वह जल्लाद हिंदु बहन-बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करता था। पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को टूटने भी नहीं देंगे और राष्ट्रविरोधी-समाजविरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे। हम धरती मां के स्वास्थ्य की भी रक्षा करेंगे और मां की स्मृतियों को भी जीवंत बनाएंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्सप्रेसवे के किनारे आजमगढ़ के सठियांव ब्लॉक के

केरमा गांव में हरिशंकरी वाटिका की स्थापना की। आजमगढ़ को 60लाख पौधे लगाने का लक्ष्य मिला था। सीएम योगी ने यहां 60 लाख वां पौधा लगाया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से इस विराट अभियान का हिस्सा बनने के लिए आजमगढ़ व प्रदेशवासियों का आभार प्रकट किया।

यह अभियान अपनी और धरती मां के प्रति कृतज्ञता का माध्यम

सीएम योगी ने कहा कि आज अयोध्या समेत कई जनपदों में भारी बारिश हो रही है। प्रातः 7 बजे से शुरू हुए कार्यक्रम में एक पेड़ मां के नाम के तहत यूपी के अंदर अब तक 22 करोड़ का लक्ष्य पूरा किया जा चुका है। 22 करोड़ पौधरोपण का मतलब यूपी के हर व्यक्ति के नाम पर लगा पौधा अपनी और धरती मां के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का माध्यम बना है। धरती हमारी मां और हम उसके पुत्र हैं। धरती केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है। दुनिया में केवल भारत में ही धरती के प्रति आत्मीय भाव देखने को मिलता है। ऋषि-मुनियों ने हमें संस्कारों से जोड़ा है। धरती मां स्वस्थ है तो हम सब स्वस्थ हैं। धरती मां बीमार हुई तो जीव सृष्टि के लिए जीवन-मरण का प्रश्न बन जाएगा। चेतावनी का संकट आ जाएगा। यह धरती मां की सेहत को सुधारने और मां की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने का कार्यक्रम है। सीएम योगी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन, अतिवृष्टि-अनावृष्टि की समस्या के समाधान के लिए पीएम मोदी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने 8 वर्ष पहले यह अभियान प्रारंभ किया था। 8 वर्ष में यूपी में 204 करोड़ पौधरोपण हुआ है। यह केवल भारत सरकार या देश की महत्वपूर्ण संस्थाएं ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं भी स्वीकार कर रही हैं कि यूपी में वनाच्छादन बढ़ा है। 2017 के पहले यूपी का वनाच्छादन मात्र 9 फीसदी था, आज यह बढ़कर 10 फीसदी हो गया। सीएम ने कहा कि उक्त अवधि से पहले के 15 वर्षों में यूपी के अंदर वन, खनन, पेशेवर माफिया के द्वारा व्यापक वन कटान और अवैध खनन से अराजकता, अव्यवस्था फैलाई गई थी। तब विकास नहीं होता था।

हमने डेढ़ साल में किए पूर्ववर्ती सरकार के पांच साल से ज्यादा काम : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

एजेंसी

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मानना था कि अन्तिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के उत्थान से ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा उनके इसी सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार महिला, किसान, युवा व मजदूर इन चार जातियों के सशक्तीकरण के लिए निरंतर काम कर रही है, जिससे विकास का उजियारा हर वर्ग तक पहुंचे।शर्मा सवाई माधोपुर में बालेर (खंडार) के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के दौरान आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सवाई माधोपुर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक धरोहर के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है। यहां का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जहां बाघों के लिए दुनियाभर में जाना जाता है, वहीं रणथंभौर का किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। सवाई माधोपुर के अमरूदों की अपनी विशेष पहचान है। शर्मा ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से गरीब और वंचित वर्ग को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाकर उनके जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी अभियान का उद्देश्य है कि प्रशासन और जनता के बीच कोई खाई नहीं हो तथा कोई भी व्यक्ति विकास की मुख्य धारा से छूट ना जाए। उन्होंने

कहा कि प्रदेशभर में इन शिविरों से आमजन के भूमि संबंधी विवादों का समाधान, नर्सरियों से पौधों का वितरण, मृदा नमूनों का संग्रहण, मृदा स्वास्थ्य कार्डों का वितरण, मंगला पशु बीमा, पशुओं की जांच, इलाज और टीकाकरण, आयुष्मान कार्ड वितरण, गरीब परिवारों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं तथा एनएफएसए सहित कई लंबित प्रकरणों का निस्तारण हो रहा है। उन्होंने कहा कि सवाई माधोपुर में इन शिविरों के माध्यम से अब तक सीमा ज्ञान के 410, रास्तों के 228, आपसी सहमति से बंटवारे के 161 प्रकरणों का निस्तारण कर स्वामित्व के 689 कार्ड वितरित, 33 हजार 414 पौधों के वितरण सहित विभिन्न जनहित के कार्य किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए कृत्संकल्पित होकर कार्य कर रही है। पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए पूर्वी राजस्थान के लिए ईआरसीपी, शेखावाटी के लिए यमुना जल समझौता, इंदिरा गांधी नहर, देवास, माही, नर्मदा सहित विभिन्न परियोजनाओं पर भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। शर्मा ने कहा कि राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू किए गए, वहीं प्रदेश को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के डेढ़ साल के कार्यकाल में एक भी पेपरलीक नहीं हुआ। हम युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए कृत्संकल्पित हैं तथा 5 साल में 4 लाख सरकारी व 6 लाख निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा रहे हैं।

त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री ने मोदी की कविता उद्धृत की

एजेंसी

नई दिल्ली। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद-बिसेसर नेभारतीय मूल के लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की एक कविता का उल्लेख किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की यह कविता आंख आ धन्य छे नामक गुजराती पुस्तक से उद्धृत की। त्रिनिदाद और टोबैगो में आयोजित सामुदायिक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने यह कविता पढ़ी। प्रधानमंत्री बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कविता उनके संघर्ष, स्मृतियों और अनुभवों की शक्ति को दर्शाती है। कविता में अतीत की यात्रा, कठिनाइयों में साथ चले लोगों की स्मृति, और उन अनुभवों की अंततः जीवन यात्रा का हिस्सा बन जाने की बात कही गई है। प्रधानमंत्री प्रधानमंत मोदी की कविता (यात्रा) का पाठ करते हुए बिसेसर ने दर्शाया कि कैसे व्यक्तिगत स्मृतियां और सामूहिक संघर्ष किसी भी व्यक्ति की चेतना में स्थायी रूप से बसे रहते हैं। यह कविता न केवल मोदी के निजी अनुभवों की झलक देती है, बल्कि प्रवासी भारतीयों को भी उनकी जड़ों से जोड़ती है।

वोटर लिस्ट संशोधन पर पप्पू यादव ने उठाए सवाल, केजरीवाल को लेकर कहा- रस्सी जल गई, ऐंठन नहीं गई

पटना। बिहार में वोटर लिस्ट संशोधन को लेकर सियासी घमासान मचा है। पूर्णिया सांसद राजेश रंजन यानि पप्पू यादव ने बिहार चुनाव से पहले भारत निर्वाचन आयोग के इस अभियान पर सवाल उठाया है। साथ ही इंडी अलायंस से नाता तोड़ने का ऐलान कर चुके आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को भी आड़े हाथों लिया। मीडिया से बात करते हुए पूर्णिया सांसद ने कहा, चुनाव आयोग आरएसएस का दफ्तर है, उसको रोकना चाहिए। जो संवैधानिक दायित्व के लिए खतरा बन जाए, उसके लिए जनता तैयार है। आज हम लोग तय करेंगे। कांग्रेस प्रभारी से भी इसे लेकर

बातचीत हुई है। चुनाव आयोग मुलाकात नहीं कर रही है वाले सवाल को लेकर उन्होंने कहा, चुनाव आयोग अलाद्दीन का चिराग है क्या? आर-पार की लड़ाई होगी। बिहार और बिहारी की अस्मिता के लिए जान भी देनी पड़ेगी तो देंगे। अरविंद केजरीवाल के बिहार चुनाव अकेले लड़ने को लेकर उन्होंने कहा, यह अच्छी बात है, चुनाव लड़ना सबका अधिकार है। वे बिहार आकर चुनाव लड़ें।केजरीवाल को लेकर पप्पू यादव ने कहा कि रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई। बिहार में महज कुछ ही महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार की विपक्षी पार्टियों ने इस कदम की तीखी आलोचना की। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिशबताया है।उन्होंने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्वाचन आयोग को बिहार की समस्त मतदाता सूची को निरस्त कर केवल 25 दिन में 1987 से पूर्व के कागजी सबूतों के साथ नई मतदाता सूची बनाने का निर्देश दिया है। चुनावी हार की बौखलाहट में ये लोग अब बिहार और बिहारियों से मतदान का अधिकार छीनने का षड्यंत्र कर रहे हैं। वहीं, कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने सवाल उठाया कि क्या 2003 के बाद से अब तक बिहार में चार-पांच चुनाव हो चुके हैं, क्या वे सब गलत हैं, अपूर्ण या अविश्वसनीय थे?

कांग्रेस-इंडी गठबंधन में सनातन धर्म का विरोध करना फैशन बन गया है: तरुण चुघ

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर 'नेम प्लेट' विवाद को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन में सनातन धर्म का विरोध करना फैशन बन गया है। उन्होंने विपक्ष को सनातन की आस्था का अपमान न करने की नसीहत दी। समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में तरुण चुघ ने कहा कि विपक्ष का दोहरा चरित्र सामने आ रहा है। वह पवित्र कांवड़ यात्रा पर राजनीति बंद करें, क्योंकि यह करोड़ों शिव भक्तों की आस्था से जुड़ा है। उन्होंने कांवड़ यात्रा को सनातन धर्म की पवित्र और कठिन धार्मिक यात्रा बताया, जो श्रावण मास में करोड़ों शिव भक्तों द्वारा की जाती है। चुघ ने विपक्ष पर वोट बैंक की राजनीति के लिए कांवड़ यात्रा और सनातन धर्म का विरोध करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, कांग्रेस और इंडी गठबंधन में सनातन धर्म का विरोध करना फैशन बन गया है। कांवड़ियों के खिलाफ अपशब्द और उनकी आस्था का अपमान बंद होना चाहिए। उन्होंने विपक्ष से अपील की कि वे धार्मिक भावनाओं का सम्मान करें और कांवड़ यात्रा जैसे पवित्र अवसरों पर राजनीति से बाज आएं। भाजपा

नेता तरुण चुघ ने विपक्ष के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) पर सवाल उठाने को लेकर भी हमला बोला। उन्होंने कहा, जब तेलंगाना, हिमाचल और कर्नाटक में विपक्ष चुनाव जीतता है, तब ईवीएम ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा में हारने पर ईवीएम को दोषी ठहराया जाता है। ईवीएम में खराबी आ जाती है। यह दोहरा मापदंड और दोहरा चरित्र देश अब जान चुका है। उन्होंने आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के भाजपा और कांग्रेस का रिश्ता प्रेमी-प्रेमिका जैसा वाले बयान का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने कभी कांग्रेस और शीला दीक्षित के खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूत होने का दावा किया था। केजरीवाल ने कहा था, मेरे पास कांग्रेस और शीला दीक्षित के खिलाफ दो बोरी सबूत हैं। आज तक उस बोरी का मुंह नहीं खुला, लेकिन बाद में उसी कांग्रेस के साथ मिलकर दिल्ली में सरकार बनाई। किसने अभी लोकसभा चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा है। जनता ने उस आपको और उस गठबंधन को करारा जवाब दिया। केजरीवाल की नैतिकता और ईमानदारी का ढोंग–यह सब कुछ दिखा है।

रामायण' से 'महाकुंभ' तक... पीएम मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो में किया इन बातों का जिक्र

एजेंसी

पोर्ट ऑफ स्पेन। प्रधानमंत्री मोदी पांच देशों की यात्रा के दूसरे चरण के तहत त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया और भारत-त्रिनिदाद और टोबैगो के संबंधों पर बात की। साथ ही उन्होंने भगवान राम से लेकर महाकुंभ और त्रिनिदाद और टोबैगो की रामलीलाओं का भी जिक्र किया।

पीएम मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय प्रवासियों की छठी पीढ़ी को ओवरसीज सिटिजनशिप ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड दिए जाने की बात की। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ खून या उपनाम से ही नहीं जुड़े हैं। आप अपनेपन से भी जुड़े हैं।

प्रधानमंत्री ने भारत की अंतरिक्ष में उड़ान का जिक्र किया। उन्होंने कहा, ÷वो समय अब दूर नहीं है कि जब कोई भारतीय चंद्रमा पर पहुंचेगा और भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा। हम अब तारों को सिर्फ गिनते

नहीं हैं, आदित्य मिशन के रूप में उनके पास जाने का प्रयास करते हैं। हमारे लिए अब चंदा मामा दूर के नहीं हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बिहार की विरासत को भारत के अलावा उसे दुनिया का भी गौरव बताया। उन्होंने कहा, ÷लोकतंत्र हो, राजनीति हो, कूटनीति हो, उच्च शिक्षा हो, बिहार ने सदियों पहले दुनिया को ऐसे अनेक विषयों में नई दिशा दिखाई थी। मुझे विश्वास है कि 21वीं सदी की दुनिया के लिए भी बिहार की धरती से नई प्रेरणाएं और नए अवसर निकलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत से गरीबी को खत्म करने का भी जिक्र किया और कहा, भारत ने दिखाया है कि गरीबों को सशक्त करके, उन्हें समर्थ करके गरीबी को हराया जा सकता है।

पहली बार करोड़ों लोगों में विश्वास जाएगा कि भारत गरीबी से मुक्त हो सकता है। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री कमला पर्साद-बिसेसर को बिहार की बेटी बताया। उन्होंने कहा, ÷त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला पर्साद-बिसेसर के पूर्वज बिहार के बक्सर से थे। कमला खुद वहां जाकर भी आई हैं और लोग उन्हें बिहार की बेटी मानते हैं। प्रधानमंत्री ने 500 साल बाद अयोध्या में रामलला की वापसी का भी जिक्र किया।

भाजपा ने स्वामी विवेकानंद के निर्वाण दिवस पर उन्हें किया नमन

एजेंसी

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने स्वामी विवेकानंद के निर्वाण दिवस पर उन्हें नमन किया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज एक्स पर कहा कि विश्व में भारतीय संस्कृति को स्थापित करने वाले, महान आध्यात्मिक गुरु और युवाओं के प्रेरणास्रोत स्वामी विवेकानंद जी के निर्वाण दिवस पर उन्हें कोटिशः नमन। उन्होंने कहा कि विश्वभर में भारतीय संस्कृति की वैभवता और महानता का बोध कराने वाले स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति को राष्ट्रनिर्माण का आधार मानते थे। उनके द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन आज देशभर में जनसेवा के क्षेत्र में अनुकरणीय योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि युवा तरुणाइयों में चरित्र निर्माण एवं राष्ट्र उत्थान की भावना जागृत करने में उनका योगदान अविस्मरणीय है।

गडकरी ने झारखंड में 3800 करोड़ रुपये के विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों की योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास

एजेंसी

रांची। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने झारखंड में 3800 करोड़ रुपये से अधिक के राष्ट्रीय राजमार्गों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। गडकरी ने इस अवसर पर राजधानी रांची को चार तोहफे भी दिए। इसमें रांची में आउटर रिंग रोड का निर्माण, इलेक्ट्रिक बस का परिचालन, रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर के पिलर पर सोहराई पेंटिग कराने और रांची-गनगडा-सिल्ली सड़क को फोरलेन बनाना शामिल है।

रातू रोड स्थित ओटीसी ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि झारखंड की तारीफ करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पीछे मोदी सरकार खड़ी है। केंद्र सरकार झारखंड के विकास के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा कि झारखंड को लेकर दो लाख करोड़ रुपये की सड़क योजनाएं बन रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के आग्रह पर आउटर रिंग रोड के निर्माण पर छह हजार करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इसका डीपीआर बनाने का निर्देश अधिकारियों को दे दिया गया है। इलेक्ट्रिक बस सेवा भी बहाल होगी। रांची में यह सेवा नागपुर के बाद देश

की दूसरी सेवा होगी। इस सेवा के शुरू होने से लोगों को 30 प्रतिशत सस्ती सेवा मिल पाएगी।गडकरी ने कहा कि देश में लॉजिस्टिक खर्च पूर्व में 16 प्रतिशत था जो घटकर अब 10 प्रतिशत रह गया है और यह अगले पांच साल में नौ प्रतिशत होगा। इससे हमारे देश का निर्यात बढ़ेगा और देश आत्मनिर्भर बनेगा। उन्होंने बताया कि अगले दो वर्षों में अमेरिका की तरह देश की सड़कें होंगी। गडकरी ने बताया कि हम देश में ग्रीन एक्सप्रेस-वे बना रहे हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि रातू रोड में लाल डामर की सड़क थी। अनशन करने के बाद इस सड़क को बनाया गया, लेकिन एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए उन्हें कोई अनशन नहीं करना पड़ा। उन्होंने गडकरी से रांची आउटर रिंग रोड, सिल्ली -अनगडा रोड, एलिवेटेड कॉरिडोर के पिलर पर सोहराई पेंटिंग कराने और रांची में एक्ट्रिक बस चलाने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सुरक्षा की गारंटी और सुशासन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य की टूटी-फूटी सड़कें अब केंद्रीय मंत्री गडकरी के प्रयास से टू-लेन और फोरलेन में तब्दिल हो रही हैं।

अमरनाथ यात्रा: जम्मू से 6411 तीर्थयात्रियों का एक और जत्था रवाना, पहले दिन 12 हजार से अधिक भक्तों ने किए दर्शन

एजेंसी

श्रीनगर। अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू से एक और जत्था भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रवाना हुआ। इस जत्थे में 6411 तीर्थयात्री शामिल थे। अधिकारियों के अनुसार, शुक्रवार सुबह भगवती नगर यात्री निवास से 291 वाहनों के दो सुरक्षा काफिलों में कुल 6411 यात्री कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुए। इनमें से 2789 यात्री बालटाल बेस कैंप की ओर जा रहे हैं, जबकि 3622 यात्री पहलगाम बेस कैंप जा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि 38 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा के पहले दिन, गुरुवार को 12300 यात्रियों ने पवित्र गुफा में दर्शन किए। यात्रा के दौरान श्रद्धालु बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों के साथ उत्साहपूर्वक तीर्थ कर रहे हैं। सुरक्षा के विषय पर तीर्थयात्रियों ने कहा, उन्हें पाकिस्तान या उसके भाड़े के एजेंटों से कोई डर नहीं है। वो भगवान शिव के आह्वान पर यात्रा कर रहे हैं और उन्हीं की कृपा में सुरक्षित महसूस करते हैं। इस साल की अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है, क्योंकि यह 22 अप्रैल के कायरतापूर्ण हमले के बाद हो रही है, जिसमें पाकिस्तान समर्थित

आतंकवादियों ने पहलगाम में कथित तौर पर धर्म देखकर 26 पर्यटकों की हत्या की थी। फिलहाल यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व स्तर पर मजबूत किया गया है। सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी और स्थानीय पुलिस की मौजूदा ताकत को बढ़ाने के लिए सीएपीएफ की 180 अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई हैं।दोनों आधार शिविरों के रास्ते में सभी शिविर और जम्मू में भगवती नगर यात्री निवास से गुफा मंदिर तक का पूरा मार्ग सुरक्षाबलों की ओर से सुरक्षित है। तीर्थयात्री बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक दो रास्तों से पहुंचते हैं, जिसमें एक पारंपरिक पहलगाम मार्ग है और दूसरा छोटा, लेकिन कठिन बालटाल मार्ग है। पहलगाम रूट पर गुफा मंदिर तक पहुंचने के लिए चंदनवारी, शेषनाग और पंचतरणी से गुजरना पड़ता है, जिसमें कुल 46 किमी की दूरी तय करनी होती है। बालटाल मार्ग का उपयोग करने वालों को गुफा मंदिर तक पहुंचने के लिए 14 किमी की पैदल यात्रा करनी पड़ती है और यात्रा करने के बाद उसी दिन बेस कैंप वापस लौटना पड़ता है।

प्रधानमंत्री मोदी को ट्रिनिडाड एंड टोबैगो का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान करने की घोषणा

एजेंसी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को ट्रिनिडाड एंड टोबैगो सरकार ने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो' देने की घोषणा की। यह घोषणा वहां की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने भारतीय प्रवासी समुदाय के बीच आयोजित एक बड़े स्वागत समारोह में की। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की ऐतिहासिक यात्रा और दोनों देशों के बीच संबंधों को सुदृढ़ करने में उनकी भूमिका की सराहना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस सम्मान के लिए ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की जनता और सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने यह घोषणा की कि अब ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में बसे भारतीय मूल के छठी पीढ़ी के लोगों

को भी ओसीआई कार्ड जारी किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के 180 वर्षों पूर्व आए भारतीय मूल के लोगों के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि उनकी यह यात्रा उस ऐतिहासिक विरासत को सम्मानित करने का अवसर है। उन्होंने भारतीय प्रवासियों की सांस्कृतिक जीवंतता और उनकी सामाजिक भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री ने 'वसुधैव कुटुंबकम' के सिद्धांत का उल्लेख करते हुए ट्रिनिडाड एंड टोबैगो को भारत की ओर से निरंतर सहयोग का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में देश ने आधारभूत संरचना, डिजिटल तकनीक, हरित ऊर्जा, अंतरिक्ष अनुसंधान, नवाचार और स्टार्टअप्स के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने बताया कि 25 करोड़ से अधिक लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला गया है और भारत शीघ्र ही विश्व की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। उन्होंने बताया कि भारत के राष्ट्रीय मिशन जैसे एआई, सेमीकंडक्टर और क्वांटम कंप्यूटिंग विकास के नए इंजन बन रहे हैं।

राज्यसभा का 268वां सत्र 21 जुलाई से

एजेंसी

नई दिल्ली। राज्यसभा का 268वां सत्र 21 जुलाई से शुरू होगा। आज जारी आधिकारिक संसदीय बुलेटिन के अनुसार, राज्यसभा सत्र 21 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कुल 21 बैठकें होंगी। संसदीय बुलेटिन के अनुसार, राष्ट्रपति ने सोमवार, 21 जुलाई, 2025 को नई दिल्ली में राज्य सभा की बैठक बुलाई है। कार्य की अनिवार्यता के अधीन, सत्र का समापन गुरुवार, 21 अगस्त, 2025 को होना निर्धारित है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के कारण 13 और 14 अगस्त को संसद की कोई बैठक नहीं होगी। आगामी मानसून सत्र ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला संसद सत्र होगा। इस ऑपरेशन को भारत ने 07 मई को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में शुरू किया था। पहलगाम में 26 लोगों की जान चली गई थी। संसद का बजट सत्र इस साल जनवरी में हो चुका है।

दिल्ली-एनसीआर में उमस से लोग परेशान, आईएमडी ने बारिश को लेकर दिया अपडेट

एजेंसी

दिल्ली। मौसम विभाग के मुताबिक, 4 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक क्षेत्र में बादलों की आवाजाही और बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इससे एक तरफ जहां अधिकतम तापमान में गिरावट आएगी, वहीं बढ़ती उमस लोगों को परेशान भी कर सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 5 जुलाई को कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की आशंका है। इसे देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दिन सुबह के समय गरज के साथ बिजली चमकने और हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी दी गई है। तापमान 36 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और 27 डिग्री न्यूनतम रहने की संभावना है। हवा में नमी की मात्रा 80 प्रतिशत से 65 प्रतिशत के बीच बनी रहेगी। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह देते हुए कहा है कि बारिश के समय पर खुले इलाकों और बिजली के उपकरणों के नजदीक न जाएं। आईएमडी के मुताबिक 4 जुलाई को भी कुछ इलाकों में गरज के साथ बारिश की संभावना है, हालांकि इस दिन कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। तापमान 37 डिग्री अधिकतम और 28 डिग्री न्यूनतम रहेगा। वहीं, 6 जुलाई को आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश हो सकती है। इस दिन अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री रह सकता है। 7 और 8 जुलाई को मौसम विभाग ने गरज के साथ बारिश की संभावना जताई है। तापमान 33 डिग्री अधिकतम और 25 डिग्री न्यूनतम रहेगा। ह्यूमिडिटी में मामूली अंतर देखा जाएगा, लेकिन गर्मी से कुछ राहत जरूर मिलेगी। 9 और 10 जुलाई को बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की उम्मीद है। हालांकि इन दोनों दिनों के लिए कोई चेतावनी नहीं दी गई है, लेकिन आसमान में बादलों की उपस्थिति और नमी के कारण वातावरण नम बना रहेगा। लगातार बारिश के चलते दिल्ली-एनसीआर के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे लोगों को तेज गर्मी से राहत मिल रही है। हालांकि, हवा में बनी अधिक नमी (ह्यूमिडिटी) के कारण उमस में इजाफा हो रहा है, जिससे लोगों को चिपचिपी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है।

कोरोना वैक्सीन ने बचाई लाखों लोगों की जान : एम्स

एजेंसी

नई दिल्ली। देश के चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना के टीकों और दिल का दौरा पड़ने के बीच कोई संबंध नहीं है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान(एम्स) ने इस प्रकार की अटकलों को खारिज करते हुए आज कहा कि कोरोना के टीकों ने लाखों लोगों की जान बचाई है। गुरुवार को एम्स में पल्मोनरी, क्रिटिकल केयर और स्लीप मेडिसिन विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. करण मदान ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कोवैक्सीन एवं कोविशील्ड कोरोना के प्रभावी टीके थे और उन्होंने मृत्यु दर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महामारी के दौरान, जीवन बचाने के लिए टीके ही एकमात्र उपाय हैं। टीकों का इस्तेमाल बड़ी संख्या में लोगों पर किया गया और उन्होंने अत्यधिक मृत्यु दर को रोकने में प्रभावी भूमिका निभाई। अब तक इस्तेमाल किए गए टीकों की समीक्षा के लिए अचानक हृदय संबंधी मौतों पर एक अध्ययन किया गया था, लेकिन अचानक हृदयाघात से होने वाली मौतों का इन टीकों के साथ कोई स्पष्ट संबंध नहीं पाया गया। वहीं, एम्स के संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉ. संजय राय ने कहा कि देश में जनवरी 2021 में वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। अब तक दुनियाभर में 13 अरब से ज्यादा डोज दी जा चुकी हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 12 वैक्सीन को मंजूरी दी है।

दिल्ली में जल और सीवरेज परियोजनाओं को दी गई नई रफ्तार : प्रवेश साहिब सिंह

नई दिल्ली। दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि राजधानी में जल और सीवरेज परियोजनाओं को मंजूरी देकर नई रफ्तार दी गई। दिल्ली सचिवालय में गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने बताया कि दिल्ली जल बोर्ड ने अपनी हालिया बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये योजनाएं न केवल लाखों लोगों को सीधे लाभ पहुंचाएंगी बल्कि यमुना नदी में प्रदूषण को कम करेंगी, जल वितरण को समान बनाएंगी और वर्षों से लंबित पुनर्वास कार्यों को गति देंगी। मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि साफ पानी और प्रभावी सीवरेज व्यवस्था सिर्फ पाइपलाइन नहीं, लोगों के जीवन की गरिमा और हक से जुड़ा मसला है। हम वर्षों से अटकी योजनाओं को फिर से जमीन पर ला रहे हैं ताकि हर नागरिक को उसका हक मिल सके। उन्होंने कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और भूमि विकास एजेंसियों की जल/सीवरेज योजनाओं को मंजूरी देने एवं क्रियान्वयन की पूरी जिम्मेदारी अब दिल्ली जल बोर्ड की है। एक अहम नीतिगत सुधार के तहत अब दिल्ली जल बोर्ड को डीडीए और अन्य भूमि विकास एजेंसियों की जल और सीवरेज योजनाओं को सीधे स्वीकृत करने और उन्हें क्रियान्वित करने की अनुमति दी गई है। उन्होंने बताया कि 2019 से पहले यह प्रक्रिया चीफ इंजीनियर (प्लानिंग) स्तर पर पूरी हो जाती थी, जिससे कार्य शीघ्र पूरे होते थे।

खंडेलवाल ने अधिकारियों के साथ चावड़ी बाजार, सीताराम बाजार एवं माता सुंदरी गुरुद्वारा क्षेत्र का निरीक्षण किया

नई दिल्ली। चांदनी चौक से सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने गुरुवार को अपने संसदीय क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चावड़ी बाजार, सीताराम बाजार एवं माता सुंदरी गुरुद्वारा क्षेत्र का निरीक्षण दौरा किया। सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने अपने निरीक्षण के दौरान दिल?ली नगर निगम अधिकारियों को चावड़ी बाजार से कुछ स्थाई अतिक्रमण हटाने के साथ ही जलबोर्ड एवं लोकनिर्माण विभाग अधिकारियों को सड़कों पर धसते सीवर एवं गड्ढे ठीक करने और पुलिस को अवैध पार्किंग एवं रिक्शा कंट्रोल करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने हौजकाजी चौक से अवैध स्कूटर पार्किंग को हटाने के निर्देशो भी दिल्ली पुलिस को दिया और सीताराम बाजार की सड़के ठीक कर रेहड़ी-पटरी वाले दुकानदारों जो स्थानीय निवासी भी हैं, उनको व्यवस्थित करने को कहा। सांसद खंडेलवाल ने दिल्ली नगर निगम की शहरी क्षेत्र उपायुक्त से माता सुंदरी रोड़ पर खासकर दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पीछे से लोकनायक अस्पताल के गेट के पास से और गुरुद्वारा साहब के आसपास के कबाड़ियों के अवैध कब्जों को हटवाने की योजना बनाने को कहा।

आआपा पार्षदो ने सफाई व्यवस्था को लेकर महापौर के कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग के नेतृत्व में गुरुवार को सिविक सेंटर में आआपा पार्षदों की बैठक हुई। बैठक के बाद आआपा पार्षद ने दिल्ली में सफाई व्यवस्था को लेकर महापौर राजा इकबाल सिंह के कार्यालय के बाहर कचरा रखकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने महापौर से इस्तीफा देने की मांग की। इस दौरान अंकुश नारंग ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि दिल्ली नगर निगम सफाई व्यवस्था पर ध्यान नही दे रही है। इसलिए आआपा पार्षद महापौर राजा इकबाल सिंह के इस्तीफे की मांग करते है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भाजपा की चार इंजन की सरकार है। फिर पूरी दिल्ली कूड़े का मैदान बनी हुई है। हर जोन में सफाई व्यवस्था चरमरा चुकी है। दिल्ली की जनता बढ़ रही बीमारियों से परेशान है।

दिल्ली-जयपुर के बीच नया ग्रीनफील्ड स्पर तैयार, यात्रा समय में कटौती : नितिन गडकरी

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि दिल्ली-वडोदरा एक्सप्रेसवे और जयपुर को जोड़ने वाला 66.9 किलोमीटर लंबा, 4-लेन वाला ग्रीनफील्ड बांदीकुई स्पर बनकर तैयार हो गया है। यह जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर दी है। उनके मुताबिक, इस परियोजना पर 2,016 करोड़ रुपये की लागत आई है। यह नया स्पर दिल्ली और जयपुर के बीच सीधी और नियंत्रित कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जिससे यात्रियों को अब लंबी और ईंधन खर्च करने वाली यात्राओं से छुटकारा मिलेगा। नितिन गडकरी के अनुसार, इस नए स्पर से दिल्ली-जयपुर के बीच यात्रा का समय 3 घंटे 45 मिनट से घटकर

केवल 3 घंटे रह जाएगा। इससे न केवल यात्रियों को सुविधा होगी, बल्कि राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-48 और एनएच-21) पर ट्रैफिक जाम की समस्या भी कम होगी। नितिन गडकरी के मुताबिक, यह परियोजना क्षेत्र में गतिशीलता को बेहतर बनाएगी और सड़क यात्रा को और सुगम करेगी। इस स्पर के बनने से जयपुर के पर्यटन स्थलों, जैसे आमेर किला और जंतर मंतर, तक पहुंच आसान होगी, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, यह क्षेत्रीय आर्थिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस परियोजना से लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी, वाहनों की टूट-फूट कम होगी और स्थानीय किसानों, खासकर फल-सब्जी उत्पादकों को दिल्ली के बड़े बाजार तक आसानी से पहुंचने का मौका मिलेगा। इससे उनकी आय बढ़ेगी और नए व्यापारिक अवसर खुलेंगे। यह परियोजना सरकार की बुनियादी ढांचा विकास की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

डीयू ने छात्रों को तीसरे वर्ष के बाद डिग्री लेकर पाठ्यक्रम छोड़ने का दिया विकल्प

एजेंसी

नई दिल्ली। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में पढ़ रहे विद्यार्थियों को तीसरे वर्ष के बाद पाठ्यक्रम से बाहर निकलने का विकल्प दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलसचिव की ओर से जारी सूचना के अनुसार, जिन विद्यार्थियों ने तीन वर्ष यानी छह सत्र पूरे कर लिए हैं, वे अब स्नातक की तीन वर्षीय उपाधि प्राप्त कर सकते हैं और आगे की पढ़ाई छोड़ सकते हैं। यह सुविधा बहु-विषयक पाठ्यक्रमों में सामान्य डिग्री तथा एकल विषय पर आधारित पाठ्यक्रमों में विशेष डिग्री (ऑनर्स) के रूप में दी जाएगी। इस विकल्प का लाभ उठाने के इच्छुक विद्यार्थी विश्वविद्यालय के

छात्र पोर्टल पर जाकर अपनी इच्छा ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने विद्यार्थियों से अनुरोध किया है कि वे इस निर्णय को लेने से पहले अपने शैक्षणिक और भविष्य के लक्ष्यों पर गंभीरता से विचार करें तथा अपने अध्यापकों और मार्गदर्शकों से सलाह लें। यह व्यवस्था नई शिक्षा नीति 2020 के उस उद्देश्य के अनुरूप है, जिसमें उच्च शिक्षा में कई प्रवेश और निकास बिंदुओं की सुविधा दी गई है, जिससे विद्यार्थियों को अपने शिक्षण पथ पर अधिक स्वतंत्रता मिल सके।

पाकिस्तान को यूएनएससी की अध्यक्षता मिलना हमारी विदेश नीति की विफलता : रणदीप सुरजेवाला

एजेंसी

बेंगलुरु। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनसीसी) की अध्यक्षता मिलने पर सवाल उठाए। उन्होंने इसे भारतीय विदेश नीति की विफलता बताया और कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह दे रहा है इसके बावजूद किसी भी देश ने भारत का समर्थन नहीं किया। रणदीप सुरजेवाला ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आतंकवादी देश पाकिस्तान को अब वैश्विक सुरक्षा का दलाल बना दिया गया है। शैतान अब कुर्सी पर बैठा है, क्योंकि कल शाम से पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कर रहा है। यह मोदी सरकार की विश्वसनीयता की बड़ी हानि और कूटनीतिक विफलता है, जिसने हमारे राष्ट्रीय हितों से समझौता किया। वैश्विक मंचों पर तस्वीरें खिंचवाने और विश्व भ्रमण से केवल शर्मिंदगी मिली है। कांग्रेस ने कहा कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है,

जिसका आतंकवादियों को पनाह देने, आतंकवाद को बढ़ावा देने और भारत में आतंकवाद एक्सपोर्ट करने का इतिहास रहा है। उसे मंगलवार 1 जुलाई 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल ली है। मोदी सरकार ने इस बारे में क्या किया? यह सब पहलगाम आतंकी हमले के कुछ सप्ताह बाद हुआ, जो स्पष्ट रूप से पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित और संचालित था। यह मोदी सरकार और उनके विदेश मंत्री एस. जयशंकर की विदेश नीति पर झूठे दावों के बावजूद हुआ, जो वैश्विक मंच पर इसे रोकने में पूरी तरह विफल रहे। उन्होंने कहा, यह सब तब हुआ, जब आज भी पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह दे रहा है, उनकी रक्षा कर रहा है, जिनमें अब मृत आतंकवादी ओसामा बिन लादेन, अब्दुल रऊफ, मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम और कई अन्य शामिल हैं। कांग्रेस नेता ने आतंकी संगठनों का जिक्र करते हुए कहा, पाकिस्तान भारत विरोधी आतंकी समूहों जैसे जैश-ए-मोहम्मद, जमात-उद-दावा, तहरीक-ए-आजादी जम्मू-कश्मीर, अल जिहाद फोर्स, जम्मू-कश्मीर स्टूडेंट्स लिबरेशन फ्रंट, तहरीक-ए-हुर्रियत कश्मीर को संरक्षण और सहायता दे रहा है।

इग्नू ने प्रो. जी. राम रेड्डी पर स्मृति व्याख्यान का किया आयोजन

एजेंसी

नई दिल्ली। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने अपने संस्थापक कुलपति प्रो. जी. राम रेड्डी की स्मृति में 30वां स्मृति व्याख्यान आयोजित कर उनके शिक्षा क्षेत्र में अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि अर्पित की। यह अवसर केवल एक स्मरण नहीं, बल्कि आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में उनके दृष्टिकोण की प्रासंगिकता पर पुनः विचार का मंच बना। कार्यक्रम में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने मुख्य व्याख्यान प्रस्तुत किया। उन्होंने भविष्य के लिए तैयार कार्यबल का निर्माण= शिक्षा, कौशल और डिजिटल परिवर्तन विषय पर अपने विचार रखे। बेरी ने कहा कि आज जब दुनिया तीव्र डिजिटल बदलावों और तकनीकी नवाचारों से गुजर रही है, भारत को ऐसी शिक्षा व्यवस्था विकसित करनी होगी जो

भारत का जनसांख्यिकीय लाभ एक बड़ी शक्ति है, पर उसे सशक्त करने के लिए उत्पादकता, समावेशन और नवाचार साथ चलने चाहिए। उन्होंने प्रो. रेड्डी को शिक्षा के लोकतांत्रीकरण का अग्रदूत बताते हुए कहा कि उन्होंने भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक बाधाओं को तोड़ते हुए शिक्षा को हर व्यक्ति की पहुंच में लाने का कार्य किया। उनकी सोच आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, जब हम भविष्य के भारत की परिकल्पना कर रहे हैं। इग्नू की कुलपति प्रो. उमा कंजिलाल ने अध्यक्षीय संबोधन में प्रो. रेड्डी की दूरदर्शी सोच को याद किया। उन्होंने बताया कि कैसे इग्नू आज ऑनलाइन शिक्षण, बहुभाषी वीडियो व्याख्यान और तकनीक आधारित पहुंच के माध्यम से देशभर के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहा है। उन्होंने कहा कि प्रो. रेड्डी का उद्देश्य शिक्षा की बाधाओं को तोड़ना था और आज हम उसी मिशन को नई तकनीक के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। कार्यक्रम के आरंभ में आयोजन समिति के अध्यक्ष और इग्नू के अंतरराष्ट्रीय प्रभाग के निदेशक प्रो. जितेंद्र श्रीवास्तव ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए प्रो. रेड्डी के योगदान को याद किया।

बेहतर सैन्य प्रशिक्षण, नवाचार व ऑनलाइन प्रणाली को सराहेगी भारतीय सेना

एजेंसी

नई दिल्ली। सैन्य क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले सैनिक प्रशिक्षण संस्थानों, सैन्य यूनिट्स एवं सेना से जुड़े अधिकारियों व जवानों को सम्मानित किया जाएगा। प्रदर्शन के आधार पर ऐसे सैनिकों, अधिकारियों, संस्थानों व यूनिट्स का चयन होगा, जिन्होंने बेहतरीन योगदान दिया है। यह सम्मान आर्मी ट्रेनिंग कमांड की वार्षिक इन्वेस्टिचर सेरेमनी में दिया जाएगा। यह सेरेमनी 3 जुलाई को आयोजित की जाएगी। यह विशेष समारोह सैन्य क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले प्रशिक्षण संस्थानों, इकाइयों एवं व्यक्तियों को सम्मानित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। प्रतिष्ठित एआरटीआरएसी इन्वेस्टिचर सेरेमनी 3 जुलाई को शिमला में आयोजित होगी। इस वर्ष के समारोह की अध्यक्षता लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा, जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ (जीओसी-इन-सी), आर्मी ट्रेनिंग कमांड द्वारा की जाएगी। सेना के मुताबिक, समारोह के दौरान पांच प्रतिष्ठानों को प्रशिक्षण, नवाचार

और सैन्य नेतृत्व के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित आर्मी कमांडर यूनिट सिटेशन से सम्मानित किया जाएगा। बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए तीन संस्थानों को फाइनेंशियल एक्सीलेंस अवॉर्ड प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ ही, भौतिक माध्यम की तुलना में ऑनलाइन प्रणाली को प्रोत्साहित करने के लिए तीन प्रतिष्ठानों को ई-ऑफिस एक्सीलेंस अवॉर्ड भी दिए जाएंगे। व्यक्तिगत श्रेणी में, तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नौ नवप्रवर्तकों को उनकी तकनीकी खोजों के लिए सम्मानित किया जाएगा। सेना का कहना है कि इससे संचालन और संगठनात्मक दक्षता में सुधार होगा। इसके अतिरिक्त, सैन्य कमांडर विशिष्ट सेवा और अपने-अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों को 'ऑन द स्पॉट' प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित करेंगे। सेना के मुताबिक, इन्वेस्टिचर सेरेमनी आर्मी ट्रेनिंग कमांड की एक गौरवशाली परंपरा है, जो भारतीय सेना में उत्कृष्टता और दृढ़ता की संस्कृति को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सम्मानित किए जाने वाले पुरस्कारों में आर्मी कमांडर यूनिट सिटेशन, वित्तीय उत्कृष्टता पुरस्कार तथा ई-ऑफिस को बढ़ावा देने के लिए विशेष पुरस्कार शामिल हैं।

इस अवसर पर भारतीय सेना के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों एवं यूनिट्स के कमांडेंट्स, वरिष्ठ सैन्य अधिकारी एवं पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। यह समारोह न केवल उत्कृष्टता को सम्मानित करता है, बल्कि सेना में उत्कृष्ट प्रशिक्षण परंपराओं को मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है।

टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के लिए नीति दिशा-निर्देशों में संशोधन का रखा प्रस्ताव

एजेंसी

नई दिल्ली। टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स (टीआरपी) का सही-सही आकलन करने के उद्देश्य से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के लिए नीति दिशा-निर्देशों में संशोधन करने जा रहा है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दो जुलाई को इस संबंध में मसौदा जारी किया। इस मसौदे में मीडिया घरानों के लिए कुछ प्रतिबंधात्मक प्रावधानों को हटाया गया है, ताकि देश में टेलीविजन दर्शकों की माप पारिस्थितिकी तंत्र को लोकतांत्रिक और आधुनिक बनाने के लिए मौजूदा एआरसी के अलावा और अधिक कंपनियों को अनुमति दी जा सके। मंत्रालय ने मसौदा जारी होने के 30 दिनों के भीतर हितधारकों और आम जनता से सुझाव आमंत्रित किए हैं। उल्लेखनीय है कि टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के लिए नीति दिशा-निर्देश 2014 में जारी किए गए थे। मंत्रालय ने बताया कि भारत में वर्तमान में लगभग 23 करोड़ घरों में टेलीविज़न हैं। जबकि वर्तमान में केवल 58,000 लोगों के घरों को ही दर्शकों के डेटा को कैप्चर करने के लिए उपयोग किया जाता है, जो कुल टीवी वाले घरों का केवल 0.025 प्रतिशत है। यह अपेक्षाकृत सीमित नमूना है। इसके अलावा, स्मार्ट टीवी, स्ट्रीमिंग डिवाइस और मोबाइल एप्लिकेशन जैसे उभरते प्लेटफार्मों पर दर्शकों की संख्या को पर्याप्त रूप से कैप्चर नहीं किया जा रहा है। मौजूदा टीआरपी सिस्टम से जुड़ी समस्याएं ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल फिलहाल टीवी रेटिंग देने वाली एकमात्र एजेंसी है।यह कनेक्टेड टीवी डिवाइस व्यूअरशिप को ट्रैक नहीं करती, जबकि यह एक बड़ा ट्रेंड है। मौजूदा नीतियों में प्रवेश संबंधी बाधाएं थीं, जो नए कंपनियों को टीवी रेटिंग क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकती थीं।

नेशनल हेराल्ड केस : सोनिया-राहुल गांधी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, ईडी का दावा - 2000 करोड़ की संपत्ति हथियाने की हुई थी साजिश

एजेंसी

नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ा दावा किया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने बताया कि कांग्रेस नेशनल हेराल्ड की करीब 2,000 करोड़ रुपये की संपत्ति हड़पना चाहती थी। ईडी की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट में कहा, नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों पर कंट्रोल करने के लिए यंग इंडियन लिमिटेड बनाने की साजिश रची गई थी, जिसमें कांग्रेस संसदीय पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी प्रमुख हिस्सेदार हैं। इसका लक्ष्य पार्टी नेतृत्व को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाना था। एएसजी राजू ने दावा किया कि कांग्रेस के कई सीनियर नेता एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को किए गए ÷फर्जी लेनदेन÷ में शामिल थे। ईडी के मुताबिक, कांग्रेस के बड़े नेताओं के निर्देश पर कुछ लोगों ने फर्जी तरीके से किराए का भुगतान किया था। इन लेन-देन के साथ फर्जी किराया रसीदें तैयार की गई थीं। ईडी ने दावा किया कि साजिश थी कि यंग इंडिया के माध्यम से 2,000 करोड़ की संपत्ति कब्जे में लेकर 90 करोड़ का कर्ज लिया जाए। ईडी ने ये भी

बताया कि कांग्रेस कमेटी ने सार्वजनिक टेंडर निकाले बिना एजीएल की संपत्ति यंग इंडिया को 50 लाख रुपये में बेच दी, जबकि एजीएल की संपत्ति 2,000 करोड़ की थी। यंग इंडिया के पास इसे चुकाने के लिए पैसे नहीं थे, जिसके बाद यह मामला कोलकाता में शेल कंपनियों तक पहुंचा। एक करोड़ रुपए का लोन यंग इंडिया को दिया गया, जबकि इसकी बैलेंस शीट नेगेटिव थी। एएसजी राजू ने कोर्ट को बताया कि ईडी की जांच में यह भी सामने आया है कि यंग इंडिया पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नियंत्रण था। दोनों ने मिलकर 76 प्रतिशत शेयर अपने पास रखे थे। वास्तव में ये कंपनियां उनके नियंत्रण में थीं और इनके संचालन के लिए वो जिम्मेदार थे।

कोरोना वैक्सीन और युवा लोगों में अचानक हार्ट अटैक को लेकर उठ रहे सवाल पर बोले विशेषज्ञ, कहा- इनके बीच कोई संबंध नहीं

एजेंसी

नई दिल्ली। कोरोना वैक्सीन और युवा लोगों की अचानक हार्ट अटैक से हो रही मौतों को लेकर उठ रहे सवाल को विशेषज्ञों ने खारिज कर दिया। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के पूर्व महानिदेशक डॉ बलराम भार्गव ने कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन और युवा लोगों में अचानक हृदय संबंधी मृत्यु के बीच कोई संबंध नहीं। आईसीएमआर के हाल ही में किए गए एक अध्ययन से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है। उन्होंने कहा कि 18 से 45 वर्ष के लोगों में हार्ट अटैक से हो रही मौतों में 50 प्रतिशत से अधिक युवा धूम्रपान करने वाले होते हैं या फिर शराब पीने की लत होती हैं। कोई मधुमेह रोग से ग्रसित होते हैं या उनमें उच्च कोलेस्ट्रॉल का स्तर होता है। निचले और मध्यम स्तर के लोगों में तम्बाकू चबाने की भी रिपोर्ट है, जिससे धमनियों में कसाव, वसा जमाव और थक्का बनने की समस्या होती है, जो कोरोनरी धमनियों को अवरुद्ध कर सकता है और दिल के दौरे का कारण बन सकता है।मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि इन दिनों एक और बड़ा जोखिम है। भारी जिमिंग और बॉडीबिल्डिंग के लिए स्टेरॉयड, हार्मोन और हर्बल सप्लीमेंट जैसे असत्यापित पदार्थों का उपयोग किया जा रहा है। जिम जाना अच्छा है, लेकिन ऐसे पदार्थों का सेवन करते हुए अचानक तीव्र कसरत शुरू करना खतरनाक है। युवाओं को सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं को अपना वजन, रक्तचाप, शुगर और कोलेस्ट्रॉल के स्तर के बारे में ध्यान रखना चाहिए। यदि वे सीमा के भीतर न हों तो उन्हें सुधारने के लिए कदम उठाने चाहिए। हानिकारक आदतों से बचना चाहिए। वहीं, नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ. वीके पॉल ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि कोरोना टीकों का परीक्षण व्यवस्थित प्रयोगशाला अध्ययनों, पशु विषाक्तता अध्ययनों और नैदानिक अध्ययनों के बाद किया गया था ।

कोलकाता गैंगरेप को 'छोटी घटना' बताकर टीएमसी नेता ने किया बेटियों का अपमानः तरुण चुघ

एजेंसी

नई दिल्ली । कोलकाता गैंगरेप मामले पर टीएमसी नेताओं द्वारा लगातार विवादित बयान दिया जा रहा है और यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल्याण बनर्जी और मदन मित्रा के बाद मानस भुनिया ने कोलकाता गैंगरेप को 'छोटी घटना' बताया। टीएमसी नेता के इस बयान पर भाजपा ने पश्चिम बंगाल सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि ममता सरकार के एक मंत्री ने बंगाल की बेटियों का अपमान किया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने से बातचीत में कहा, बंगाल में बेटियों के खिलाफ अपराध लगातार हो रहे हैं और ऐसे जघन्य कृत्य को 'छोटी घटना' बताकर ममता सरकार के एक मंत्री ने बंगाल और भारत की बेटियों का अपमान किया है। इस तरह के बयान से ममता सरकार की बेटियों की सुरक्षा के प्रति असंवेदनशीलता सबके सामने आ गई है। अपराधी पर पहले से चार एफआईआर दर्ज थे, इसके बावजूद उसे कॉलेज में नौकरी दी गई। ये

अलावा कॉलेज के प्रबंधक की भी जांच होनी चाहिए। बंगाल की जनता इस लूटेरी और अपराधी सरकार को कठोर सजा देगी।' कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे के 'आरएसएस' पर टिप्पणी को लेकर तरुण चुघ ने निशाना साधा। उन्होंने कहा, 'कांग्रेस के नेता तानाशाही सोच से गहराई से प्रभावित हैं। इसलिए वे प्रतिबंध, आपातकाल, देश को जेल में बदलने, नेताओं को गिरफ्तार करने, संविधान को दबाने, लोकतंत्र पर हमला करने और संस्थाओं का अपमान करने की बात करते हैं। राहुल गांधी ने कांग्रेस में एक नया फैशन शुरू किया है।' उन्होंने आगे कहा, 'आरएसएस जैसे राष्ट्रवादी और समाज को जोड़ने वाले संगठन पर प्रतिबंध की बात करना कांग्रेस की राष्ट्रविरोधी और सनातन विरोधी मानसिकता का प्रमाण है। आरएसएस ने समाज को जोड़ा है और वे समाज में सेवा का पर्याय बने हैं। गांधी परिवार और कांग्रेस की चार पीढ़ियों ने हमेशा भारत की सनातन ताकत को कुचलने का प्रयास किया है। उन्होंने आरएसएस को रोकने के लिए प्रतिबंध लगाए, लेकिन संघ प्रखर राष्ट्रवाद, देशभक्ति और सेवा कार्यों के कारण एक नायक के रूप में स्थापित है। तरुण चुघ ने केंद्र सरकार के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा, 'पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की प्रोत्साहन योजना युवाओं के लिए आशा की नई किरण बनी है। ये केवल आंकड़ों की बात नहीं है बल्कि भारत के आत्मनिर्भर भविष्य की बुनियाद है। पीएम मोदी ने युवाओं के सपनों को नई उड़ान देने का ऐतिहासिक काम किया है।

भारत गौरव डीलक्स एसी पर्यटक ट्रेन 25 जुलाई से करेगी 'श्रीरामायण यात्रा' की शुरुआत

एजेंसी

नई दिल्ली। भगवान श्रीराम के भक्तों के लिए एक बार फिर सौभाग्य का अवसर आया है। भारतीय रेल ने एक बार फिर 'भारत गौरव डीलक्स वातानुकूलित पर्यटक रेलगाड़ी' के माध्यम से 'श्रीरामायण यात्रा' को प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। यह विशेष तीर्थ यात्रा 25 जुलाई को दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से प्रारंभ होकर 17 दिनों की अवधि में भगवान श्रीराम के जीवन से संबंधित प्रमुख स्थलों की यात्रा कराएगी। रेल मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि इस यात्रा का आयोजन भारतीय रेलवे की सहयोगी संस्था भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम द्वारा भारत सरकार की 'देखो अपना देश' तथा 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' योजनाओं के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य देश के भीतर धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहन देना है। यात्रा में श्रद्धालु अयोध्या, नंदीग्राम, सीतामढ़ी, जनकपुर, बक्सर, वाराणसी, प्रयागराज, श्रृंगवेरपुर, चित्रकूट, नासिक, हम्पी, रामेश्वरम होते हुए दिल्ली वापस लौटेंगे। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर, हनुमानगढ़ी, राम की पैड़ी का दर्शन कराया जाएगा। नंदीग्राम में भारत मंदिर, सीतामढ़ी में माता सीता का जन्मस्थल और जनकपुर का राम जानकी मंदिर सड़क मार्ग से दर्शन कराया जाएगा। बक्सर में रामरेखा घाट और रामेश्वरनाथ मंदिर, वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर, तुलसी मंदिर, संकट मोचन हनुमान मंदिर और गंगा आरती का कार्यक्रम होगा। प्रयागराज, श्रृंगवेरपुर और चित्रकूट का भ्रमण सड़क मार्ग से कराया जाएगा। इसके बाद नासिक में त्र्यंबकेश्वर मंदिर और पंचवटी क्षेत्र, हम्पी में अंजनेय पर्वत, विट्ठल मंदिर तथा विरुपाक्ष मंदिर दिखाए जाएंगे। अंतिम चरण में रामेश्वरम में रामनाथस्वामी मंदिर और धनुषकोड़ी का दर्शन होगा। इस सम्पूर्ण यात्रा में यात्री लगभग सात हजार छह सौ किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। भारत गौरव डीलक्स वातानुकूलित रेलगाड़ी में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी की यात्रा सुविधा उपलब्ध है। इस रेलगाड़ी में कुल डेढ़ सौ यात्रियों के बैठने की व्यवस्था है। रेलगाड़ी में दो भोजनालय, आधुनिक रसोईघर, स्नानागार, सेंसर युक्त शौचालय, पैर दबाने की मशीन, प्रत्येक कोच में सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा गार्ड जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

संपादक की कलम से

एचआईवी संक्रमण से मुक्ति की जंग अब भी अधूरी

आज जब दुनिया स्वास्थ्य सुरक्षा, जैविक आपदाओं और महामारी नियंत्रण के नए अध्यायों से गुजर रही है। आज यदि एक प्रभावी एड्स वैक्सीन विकसित होती है और भारत तक उसकी पहुँच सुनिश्चित होती है, तो इसके बहुआयामी सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। भारत में लगभग चौबीस लाख लोग एचआईवी से संक्रमित हैं, जिनमें से अनेक ग्रामीण, आर्थिक रूप से कमजोर और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों से हैं। वैक्सीन उपलब्ध होने से संक्रमण दर में नाटकीय गिरावट संभव है, जिससे स्वास्थ्य तंत्र पर बोझ घटेगा, जीवन प्रत्याशा बढ़ेगी और सामाजिक-आर्थिक विकास को गति मिलेगी। विशेषकर वाणिज्यिक यौनकर्मियों, ट्रांसजेंडर समुदाय, समलैंगिक पुरुषों और नशे की लत के शिकार व्यक्तियों जैसे उच्च जोखिम वाले समूहों को दीर्घकालिक संरक्षण प्राप्त होगी। यह वैक्सीन केवल स्वास्थ्य संकट का समाधान नहीं होगी, बल्कि यह सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम होगी।

कोविड महामारी के अनुभव ने यह सिखाया कि जब विज्ञान, सरकार और समाज एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो असंभव भी संभव हो सकता है। मात्र एक वर्ष में कोविड की वैक्सीन बन गई, जबकि एचआईवी जैसी महामारी को चार दशक बीत जाने के बावजूद अब तक कोई प्रभावी टीका नहीं मिल सका है। यह तुलना यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या एचआईवी से जुड़ी वैक्सीन अनुसंधान को वह राजनीतिक इच्छाशक्ति, आर्थिक संसाधन और जन समर्थन मिला जो कोविड के मामले में मिला था?

ग्रामीण क्षेत्रों, अशिक्षित जनसमूह और ट्रांसजेंडर समुदाय जैसे संवेदनशील वर्ग आज भी भेदभाव, कुप्रचार और अज्ञानता का शिकार हैं। यह वायरस शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देता है, जिससे सामान्य बीमारियां भी जानलेवा साबित हो सकती हैं। यदि समय रहते इसका पता न चले और इलाज न हो, तो एड्स होने पर जीवन की संभावना कम हो जाती है।

साथ ही, यह संक्रमण असावधान यौन संबंध, संक्रमित सुई का उपयोग, और रक्त संचरण के जरिए तेजी से फैल सकता है। इसलिए एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसका खतरा अभी भी कम नहीं हुआ है, और इसके प्रसार को रोकने के लिए सतत जागरूकता, सुरक्षित व्यवहार, और अनुसंधान की जरूरत है । आज के डिजिटल युग में जहां सूचना की पहुंच आसान हो गई है, वहीं एड्स से जुड़ी भ्रांतियां और कलंक अब भी मिट नहीं सके हैं। यही वह मानसिक दीवारें हैं जिन्हें तोड़ना, एक प्रभावी वैक्सीन की खोज से भी ज्यादा जरूरी हो चला है। आज के युवा जागरूक, तकनीकी रूप से सशक्त और सामाजिक रूप से अधिक संवेदनशील हैं। उन्हें स्कूलों, कॉलेजों और सोशल मीडिया मंचों पर एचआईवी के बारे में खुलकर संवाद करना चाहिए। सुरक्षित यौन व्यवहार, नियमित जांच और संक्रमितों के साथ करुणामय व्यवहार को सामान्य बनाना होगा। यही वह सामाजिक आधार होगा जिस पर कोई भी वैक्सीन कार्यक्रम सफल हो सकता है ।

आज के परिप्रेक्ष्य में, जब भारत वैश्विक जैव-प्रौद्योगिकी केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, यह बेहद आवश्यक है कि सरकार और नीति-निमार्ता एचआईवी वैक्सीन अनुसंधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दें और इसके लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता सुनिश्चित करें। इसके साथ ही जनस्वास्थ्य ढांचे को मजबूत बनाना होगा ताकि बेहतर परीक्षण, उपचार और रोकथाम की सुविधाएं हर स्तर पर उपलब्ध हो सकें। विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित वर्गों तक स्वास्थ्य शिक्षा और संसाधनों की सहज पहुँच सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि वे भी समय पर जानकारी और सहायता प्राप्त कर सकें। साथ ही, एड्स से जुड़े सामाजिक कलंक और भेदभाव को मिटाने के लिए व्यापक राष्ट्रीय जन जागरण अभियान चलाना होगा, जिससे समाज में समावेशन और संवेदनशीलता बढ़े तथा संक्रमितों को सम्मान और सहयोग मिल सके।आम आदमी से अपेक्षा की जाती है। कि वह एड्स से जुड़े मिथकों और भ्रांतियों को दूर करने में सक्रिय भूमिका निभाए। वे सही जानकारी प्राप्त करके अपने परिवार और समाज में जागरूकता फैलाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार अपनाएं और समय-समय पर एचआईवी परीक्षण करवाएं। साथ ही, एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति और सम्मान बनाए रखें, उनके साथ भेदभाव या कलंक से बचें। सोशल मीडिया और अपने परिचितों के बीच सही संदेश फैलाकर वे इस बीमारी के खिलाफ सामूहिक लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। यही सहयोग और समझदारी ही एड्स मुक्त समाज के निर्माण की नींव रख सकती है। आज के युग में, जब विज्ञान ने चमत्कार करने की क्षमता दिखाई है, तब यह और जरूरी हो गया है कि हम एचआईवी वैक्सीन पर जन-ध्यान केंद्रित करें।यदि हम आज निर्णय लें कि भविष्य एड्स-मुक्त होना चाहिए, तो विज्ञान, समाज और शासन झ तीनों मिलकर वह भविष्य रच सकते हैं।

विपक्ष की ताकत ने लोकतंत्र को बचा लिया

बिहार में चुनाव से पहले लोकतंत्र को कुचलने की बड़ी तैयारी चल रही थी, जिसे विपक्ष ने रोक लिया है। अक्टूबर-नवंबर में होने वाले चुनाव से पहले 25 जून से 26 जुलाई तक मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चुनाव आयोग ने शुरू किया। लेकिन यह फैसला लगातार विवादों में था और विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा था कि बिहार में करोड़ों मतदाता आखिर कहां से उन चुनिंदा दस्तावेज को उपलब्ध करा पाएंगे, जिन्हें दिखाने के बाद ही उनके नाम मतदाता सूची में शामिल करने की शर्त चुनाव आयोग ने रखी थी। अगर ये दस्तावेज नहीं दिखाए जा सके तो फिर आयोग उन्हें अवैध करार देता। यानी एक साथ करोड़ों लोग मतदान के अधिकार से वंचित रह जाते, इस पर विपक्ष ने शुरू से कड़ी आपत्ति दर्ज की थी, चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी की थी। अब विपक्ष की मुहिम रंग लाई है। चुनाव आयोग को अपने इस बड़े फैसले को लगभग पलटना पड़ा है और इसका विज्ञापन बाकायदा अखबारों में दिया गया है। अह्लरङ्ग फीं - कंगना और प्रियंका आयोग ने अब कहा है कि जिन 11 दस्तावेज की सूची दी गई थी उनमें से अगर एक भी कागज किसी के पास नहीं है तब भी उसका गणना प्रपत्र यानी एन्यूमरेशन फॉर्म जमा हो सकता है। इससे साफ पता चलता है कि चुनाव आयोग ने जो शुरूआती तेवर दिखाए थे वह अब ढीले पड़ चुके हैं। वैसे भी चुनाव आयोग का यह फैसला अटपटा है, क्योंकि हिंदुस्तान में आजादी के बाद से नागरिक को मतदान का अधिकार मिला और इसके लिए व्यवस्था की गई कि चुनाव आयोग मतदाता के दरवाजे तक जाकर उसे यह अधिकार

सौंपेगा। यही असली लोकतंत्र था, लेकिन अब इसमें उल्टी गंगा बहाते हुए चुनाव आयोग ने मतदाता पर ही यह जिम्मेदारी डाल दी कि वह फार्म भरे, दस्तावेज दिखाए और अपने वैध मतदाता होने को साबित करे। बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का आदेश जिस तरह आया और उस पर काम शुरू भी हुआ तो कई सवाल खड़े हो गए। इसे नोटबंदी और लॉकडाउन यानी देशबंदी के बाद वोटबंदी कहा जा रहा था। हालांकि यह केवल शब्दों की तुकबंदी नहीं थी, बल्कि इसके पीछे लोकतंत्र पर पड़ने वाली चोट को लेकर गहरी चिंता थी। भाजपा की आंखों पर तो इस समय सत्ता की पट्टी बंधी हुई है, इसलिए उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि करोड़ों लोग अगर चंद कागजात की वजह से वोट देने का अधिकार खो देते हैं, तो इसका कितना बड़ा नुकसान होगा। भाजपा को यह लगा होगा कि गरीब, अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़े वर्ग के वोट बड़ी संख्या में कटेंगे और उसका नुकसान केवल महागठबंधन को होगा, लेकिन हो सकता है कि दूसरे के लिए खोदे जा रहे गड्ढे में खुद भाजपा भी धंस जाए। एनडीए में भाजपा के साथी दल भी इस कवायद से होने वाले नुकसान को समझ रहे थे, लेकिन खुल कर कहने की हिम्मत नहीं दिखा रहे थे। खास तौर पर जनता दल यूनाइटेड के कई नेताओं का मानना था कि इस तरह की दस्तावेज की शर्तों से उनके अति पिछड़े और महिला वोटरों पर काफी बुरा असर पड़ेगा। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने सरकारी कर्मचारी/पेंशनर पहचान पत्र, जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, वन अधिकार और ओबीसी, एससी, एसटी प्रमाणपत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, पारिवारिक रजिस्टर, और जमीन या मकान आबंटन प्रमाणपत्र इन दस्तावेज के आधार पर वोटर को वैध या अवैध निश्चित करने का फैसला लिया। इसमें कहीं भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, मनरेगा या राशनकार्ड का जिक्र नहीं था। जबकि हिंदुस्तान की कम से कम 90 प्रतिशत आबादी अपनी पहचान बताने के लिए इन्हीं में से किसी एक कागज को दिखाती है। कोरोना वैक्सीन लगवाने से लेकर, स्कूल-कॉलेज में दाखिला, बैंक खाता खोलने, पासपोर्ट बनवाने या हवाईजहाज से सफर करने तक हर जगह पहचान के नाम पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशनकार्ड ही दिखाया जाता है। जिन दस्तावेज को रहने, खाने, काम करने, सफर करने, आजीविका के लिए जरूरी माना गया, उनमें से किसी को भी वोट डालने के लिए जरूरी क्यों नही माना गया, यह सवाल भी उठा। अगर चुनाव आयोग किसी को वोट देने के योग्य नहीं मानेगा, तो इसका मतलब है कि वह इन्हें भारत का नागरिक भी नहीं मानेगा। इसमें एक बड़े चुनावी घोटाले की बू आई, जिसके बाद ही विपक्ष ने बड़ी तेजी से इस मसले पर मोर्चा खोला और अब इसमें उसे जीत भी मिली है। 25 जून से लागू हुए इस आदेश में रोजाना की तब्दीलियां हो रही हैं, जो बता रही हैं कि इस फैसले को हड़बड़ी में लिया गया है। ठीक वैसे ही जैसे आधी रात को संसद लगाकर जीएसटी तो लागू की गई थी, फिर रोजाना नियम बदले जाते थे। जब नोटबंदी लागू की गई, उसके बाद भी यही आलम रहा कि बार-बार नियम बदले गए और अब मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण अभियान में भी यही हो रहा है। ताजा बदलाव यही है कि अब दस्तावेज दिखाना ही जरूरी नहीं है। मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग के तेवर कई बार ढीले पड़े हैं लेकिन याद रखने की बात यह है कि अब भी इसने इसमें एक पेच लगा रखा है। चुनाव आयोग के विज्ञापन में यह बात बताई गई है कि अगर आप जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराते हैं तो निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी यानी ईआरओ को आवेदन को प्रोसेस करने में आसानी रहेगी। इसके ठीक बाद चुनाव आयोग का विज्ञापन कहता है कि अगर आप जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाते हैं तो निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी यानी ईआरओ द्वारा स्थानीय जांच या अन्य दस्तावेज के साक्ष्य के आधार पर निर्णय लिया जा सकेगा।

यानी अब दस्तावेज देना जरूरी तो नहीं रहा लेकिन अगर चुनाव आयोग का अधिकारी यह मान ले कि आपको दस्तावेज की जरूरत है तो उसे देना पड़ेगा। यानी खिलवाड़ की गुंजाइश अब भी है, मगर इस बीच बिहार में 9 जुलाई को मतदाता सूची अपडेशन के खिलाफ चक्काजाम का ऐलान विपक्ष ने किया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस मामले में तीखे तेवर दिखा रहे हैं। कांग्रेस, राजद, वामदल समेत सारा विपक्ष ताल ठोंक कर मैदान में आ चुका है। तो अब उम्मीद बंध गई है कि बिहार में चुनाव की वो चोरी नहीं हो पाएगी, जिसके आरोप राहुल गांधी ने महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव में लगाए हैं और बिहार में इसी की आशंका जाहिर की थी।

संविधान की प्रस्तावना के साथ न हो खिलवाड़

आज के भारत में भारतीय संविधान की प्रस्तावना मेंधर्मनिरपेक्ष' औरसमाजवादी' शब्दों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ-भाजपा के समन्वित हमले को एक च्वहसज के रूप में वगीर्कृत करना गलत होगा इ८ - जगदीश रत्तनानी 5 ख४ह्म८ 2025 2:45 अट - जगदीश रत्तनानी यह वह बहुमूल्य विरासत है जिसे अब नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी तरह का एक प्रयास 2015 में देखा गया था जब केंद्र सरकार ने विज्ञापन जारी किया था जिसमें प्रस्तावना की एक छवि को चित्रित किया गया था लेकिनसमाजवादी' औरधर्मनिरपेक्ष' शब्दों के बिना। इसके तुरंत बाद भाजपा नेताओं अरुण जेटली, एम. वेंकैया नायडू और अमित शाह ने इस बात से इनकार किया कि प्रस्तावना में संशोधन करने का कोई कदम उठाया गया है। अह्लरङ्ग फीं - विनाश को विस्तार देते युद्ध! आज के भारत में भारतीय संविधान की प्रस्तावना मेंधर्मनिरपेक्ष' औरसमाजवादी' शब्दों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ-भाजपा के समन्वित हमले को एक च्वहसज के रूप में वगीर्कृत करना गलत होगा। यह एक सोचा-समझा एजेंडा है जो न तो राष्ट्र की भलाई करता है और न ही आरएसएस-भाजपा के हित में है। वास्तव में यह केवल उन व्यापक आशंकाओं की पुष्टि करता है कि आरएसएस-भाजपा संविधान की मूल संरचना के साथ खेलने के नए तरीकों की तलाश कर रहा है जो लंबे समय से प्रचारित इस दृष्टिकोण को और वजन देता है कि आरएसएस ने वास्तव में

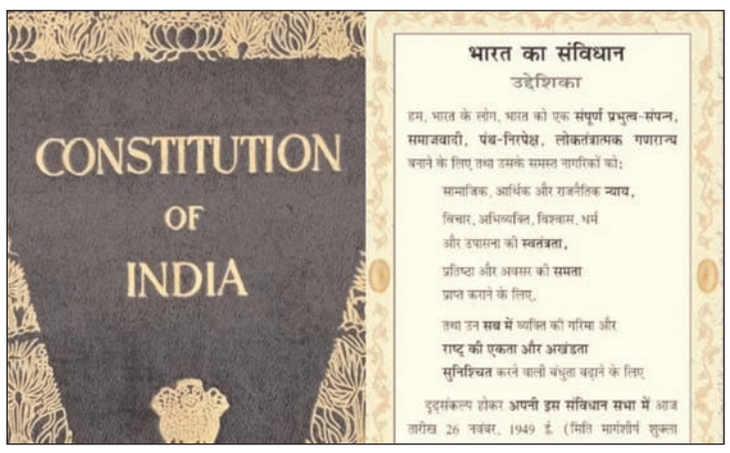

डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को कभी स्वीकार नहीं किया। यह उसचार सौ पार' के असफल अभियान की भी याद दिलाता है जिसमें भाजपा ने 2024 के आम चुनावों में तीन-चौथाई बहुमत की मांग की थी। यह संविधान के साथ छेड़छाड़ करने और उसके चरित्र को बदलने वाली संख्या थी। इस अभियान की असफलता ने भाजपा के इरादों पर पानी फेर दिया था। अगर यह लक्ष्य आज भी जारी है तो यह केवल विभाजनकारी एजेंडे की बात करता है जिसे आपातकाल का हवाला देकर भारत के संविधान सेसमाजवादी' औरधर्मनिरपेक्ष' को हटाने या मिटाने की कोशिश से छिपाया नहीं जा सकता। अह्लरङ्ग फीं - ललित सुरजन की कलम से - यात्रा वृतांतः कुछ इंदौर, कुछ उज्जैन इस अभियान को चलाकर भाजपा बड़े व्यवसायों के शक्तिशाली हितों से जुड़ी पार्टी के रूप में अधिक देखे जाने का खतरा उठा रही है जो कल्याणवाद से दूर हो रही है और उन चुने हुए क्रोनी पूंजीपतियों की मजबूत पकड़ में है जो 2014 में पार्टी के केंद्रीय सत्ता में आने के बाद से मोटे हो गए हैं। नीतियों ने असमानता को बढ़ाया है, बेरोजगारी को बढ़ाया है और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) जैसे उपहारों को बढ़ावा दिया है जिसे सरकार द्वाराखाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक कल्याण योजनाओं में से एक' के रूप में वर्णित किया गया है।

पीएमजीकेएवाई 2024-2028 से पांच साल की अवधि में 11.80 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित कुल लागत पर 80 करोड़ से अधिक भारतीयों को मुफ्त अनाज प्रदान करता है।

यदि यह योजना (और कई अन्य) कल्याणकारी राज्य के आदर्शों में विश्वास नहीं दिलाती है तो इसका क्या अर्थ है? क्या ये खैरात जब अमीर समर्थक नीतियां जोर पकड़ती हैं तब गरीबों को चुप रखने के लिए है? क्या नीति निर्माण के केंद्र में बेईमानी है या वास्तव में भारत की स्थिति इतनी विकट है कि इस योजना से लाभान्वित होने वाला 70 प्रतिशत हिस्सा मुफ्त अनाज के बिना नहीं रह सकता है? प्रधानमंत्री के विचारों से तस्वीर और जटिल हो जाती है। उदाहरण के लिए कई राज्यों में महिलाओं के लिए गतिशीलता और आर्थिक सशक्तिकरण को सक्षम बनाने वाली मुफ्त सार्वजनिक बस सवारी के खिलाफत की नीति। तो आरएसएस-भाजपा समान न्याय और पुनर्वितरण की विचारधारा के पक्ष में हैं या उसके खिलाफ हैं? अह्लरङ्ग फीं - नोटबंदी से वोटबंदी तक हालांकि यह सच है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक काला अध्याय बने आपातकाल के दौरान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की प्रस्तावना मेंसमाजवादी' औरधर्मनिरपेक्ष' शब्द जोड़े गए थे लेकिन यह सच नहीं है कि ये मूल्य संविधान की भावना या स्वभाव के खिलाफ जाते हैं। प्रभावी रूप से संशोधन के ये एकमात्र हिस्से हैं जो आज 50 साल बाद भी अधोरेखित हैं। संशोधन के अन्य हिस्सों को निरस्त कर दिया गया है या हटा दिया गया है लेकिन प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द बने रहे क्योंकि वे भारत के संविधान के व्यापक रूप से स्वीकृत लोकाचार को सुदृढ़ और उजागर करने में मदद करते हैं। 7वीं, 8वीं और 9वीं लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान पर अपनी लोकप्रिय पुस्तकों के लिए जाने जाने वाले संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी. कश्यप ने लिखा हैः... (दो शब्दों के) जोड़ने का प्रभाव केवल उस बात की पुष्टि और स्पष्टीकरण देने का था जिसे संविधान की मूल विशेषता के रूप में पहले से मौजूद माना जाता था। कश्यप लिखते हैं कि 1974 में सेंट जेवियर कॉलेज सोसाइटी बनाम गुजरात राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था किहालांकि संविधान धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात नहीं करता है लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि संविधान निमार्ता ऐसे राज्य की स्थापना करना चाहते थे'। इसके अलावा जैसा कि संविधान नोट करता है, विशेष रूप से धर्मनिरपेक्षता एक मौलिक अधिकार के रूप में धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी में निहित है। समाजवाद शब्द के लिए भी यही बात है क्योंकि जब सभी नागरिकों कोसामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक' न्याय सुरक्षित करने का संकल्प लिया गया औरस्थिति और अवसर की समानता' के विचार को स्वयं प्रस्तावना ने अपना उच्च आदर्श बताया था ।

अह्लरङ्ग फीं - कंगना और प्रियंका

सुबह खाली पेट सबसे पहले क्या खाना चाहिए? जानिए आयुर्वेद क्या कहता है

सुबह का रूटीन कैसा हैउसका असर पूरे दिन की सेहत और एनर्जी लेवल पर पड़ता है. खासकर खाली पेट उठते ही क्या खाया जाए ये तय करता है कि आपकी पाचन क्रिया, मेटाबॉलिज्म, त्वचा, और मानसिक ऊर्जा कैसी रहेगी. आयुर्वेद और न्यूट्रिशन दोनों ही इस बात पर जोर देते हैं कि सुबह का पहला आहार हल्का, पौष्टिक और शरीर को ह्लजगानेह्व वाला होना चाहिए. आइए जानते हैं, दोनों दृष्टिकोण से सुबह खाली पेट क्या खाना या पीना सबसे फायदेमंद होता है.

दिल्ली सरकार के आयुर्वेद विभाग में चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉ. आर.पी पराशर बताते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार सुबह का समय वात और कफ दोष के संतुलन का होता है. सुबह उठते ही शरीर ठंडा, सुस्त और धीमा होता है, इसलिए ऐसे फूड लेने चाहिए जो शरीर को गर्मी दें, पाचन को धीरे से एक्टिव करें और आंतों की सफाई में मदद करें.

1 -गुनगुना पानी

आयुर्वेद में दिन की शुरूआत एक या दो गिलास गुनगुने पानी से करने की सलाह दी जाती है. इसमें नींबू का रस और थोड़ा सा शहद मिलाकर पीना शरीर से टॉक्सिन्स निकालने में मदद करता है. यह मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करता है और कब्ज से भी राहत दिलाता है.

2-भीगा हुआ त्रिफला या जीरा पानी:

रातभर भिगोकर रखे गए त्रिफला पाउडर का पानी या जीरा पानी सुबह पीना शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है. यह लिवर को साफ करता है और गैस, एसिडिटी से भी राहत दिलाता है.

3-भीगे हुए बादाम और किशमिश:

रातभर भिगोए हुए 45 बादाम और कुछ किशमिश खाना आयुर्वेद में बेहद पौष्टिक माना गया है. बादाम दिमाग के लिए फायदेमंद हैं और किशमिश शरीर में आयरन और एनर्जी का स्तर बढ़ाती है.

न्यूट्रिशन की रायः सुबह शरीर को हाइड्रेट और एनर्जाइज करना जरूरी है

न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि सुबह उठते ही शरीर डिहाइड्रेटेड होता है और उसे नमी और पोषण की जरूरत होती है. इसलिए सबसे पहले कुछ ऐसा दिया जाए जिससे शरीर को ऊर्जा मिले और मेटाबॉलिज्म अच्छे से शुरू हो.

1- नींबू पानी या डिटॉक्स ड्रिंकः

गुनगुने पानी में नींबू का रस और चुटकी भर सेंधा नमक मिलाकर पीना सुबह की सबसे बेस्ट शुरूआत मानी जाती है. यह शरीर को रीहाइड्रेट करता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है और लिवर को सपोर्ट करता है.

2-भीगा हुआ चिया सीड्स पानी या मेथी पानीः

चिया सीड्स में फाइबर और ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है जो पेट को साफ रखने में मदद करता है. वहीं मेथी पानी डायजेशन के लिए अच्छा माना जाता है

राजनाथ सिंहः रक्षा, राष्ट्रीयता और राजनीतिक कौशल के प्रतीक

-ललित गर्ग-

भारत के राजनीतिक आकाश पर जिन व्यक्तित्वों ने अपनी सादगी, दृढ़ता, राष्ट्रभक्ति और कर्मठता से अमिट छाप छोड़ी है, उनमें राजनाथ सिंह का नाम शीर्ष पर आता है। राजनाथ सिंह आज देश के रक्षा मंत्री के रूप में भारत की सुरक्षा नीति, सामरिक रणनीति और आत्मनिर्भर रक्षा तंत्र के मजबूत स्तंभ बन चुके हैं। उनका राजनीतिक जीवन एक प्रेरणा की तरह है-जहां संघर्ष है, सिद्धांत हैं, और राष्ट्रहित सर्वोपरि है। उनकी लोकप्रियता एवं राजनीतिक कद यूं ही शिखरों पर आरुढ़ नहीं हुआ है, भारत के नवनिर्माण की उनकी प्रभावशाली शैली इसका कारण है। एक तरफ उन्होंने भारत की आजादी के अमृतकाल में रक्षा क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भरता बल्कि निर्यातक की भूमिका निर्मित की है, वही दूसरी ओर स्वराज्य, नये भारत-विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाये हैं।

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में चीन के पोर्ट सिटी किंगदाओ में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब करते हुए संयुक्त घोषणापत्र में हस्ताक्षर करने से मना कर न केवल पाकिस्तान और चीन को नये भारत का कड़ा संदेश दिया, बल्कि दुनिया को भी जता दिया कि भारत आतंकवाद को पोषित एवं पल्लवित

करने वाले देशों के खिलाफ अपनी लड़ाई निरन्तर जारी रखेगा। राजनाथ सिंह जैसे साहसी, निर्भीक एवं कद्दावरी नेताओं के कारनामों को दुनिया देख रही है, भारत अब पुराने वाले भारत नहीं रहा, जिसे दबाया जा सकता है। यह नया भारत है, जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नई करवटें ले रहा है। इसका नवनिर्माण हो रहा है। आज पूरी दुनिया में भारत की विश्वसनीयता है, राजनाथ सिंह ने स्वदेशी रक्षा उत्पादों की दृष्टि से दुनिया में इस विश्वसनीयता को निर्मित किया है। भारत के रक्षा उत्पाद दुनियाभर में निर्यात हो रहे हैं, उनकी गुणवत्ता, प्रभावशीलता एवं पूर्णता में दुनिया का विश्वास बढ़ रहा है, जो एक क्रांतिकारी उपलब्धि है ।मेक इन इंडियाह्व दुनिया में परचम फहरा रहा है, सफलता की नई कहानी लिख रहा है।

राजनाथ सिंह ने चीन और पाकिस्तान जैसे बाहरी खतरों के विरुद्ध रणनीतिक दृष्टिकोण ही नहीं अपनाया, बल्कि भारतीय रक्षा तंत्र को भी आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस कार्य किए हैं। रक्षा उत्पादन नीति के अंतर्गत उन्होंने कई विदेशी उपकरणों की आयात पर रोक लगाई और 100 से अधिक रक्षा सामग्रियों कोनिषिद्ध सूचीह्व में डालते हुए भारत में ही निर्माण को प्राथमिकता दी ।मेक इन इंडियाह्व अभियान को बल देते हुए उन्होंने स्वदेशी फाइटर जेट तोप, और ड्रोन तकनीक को प्रोत्साहित किया। देश के निजी उद्योगों को भी उन्होंने रक्षा क्षेत्र में निवेश के लिए प्रेरित किया और डीआरडीओ के साथ साझेदारी के नए मॉडल लागू किए।

ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में उनकी दूरदृष्टि ने भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने का मार्ग दिया है। हाल ही में 2000 करोड़ के ड्रोन प्रोत्साहन पैकेज के अंतर्गत उन्होंने न केवल सैन्य उपयोग के लिए बल्कि कृषि, ट्रैफिक प्रबंधन और आपदा राहत जैसे क्षेत्रों के लिए भी ड्रोन विकास को गति दी है।

पाकिस्तान के संदर्भ में उनका रुख अत्यंत स्पष्ट रहा है-ह्लबातचीत तब ही संभव है जब आतंकवाद बंद हो और पाकिस्तान अपने गुनाह स्वीकार करे।ह्व उन्होंने यह भी कहा कि यदि पाकिस्तान से कोई संवाद होगा, तो वह केवल पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) पर होगा। यह उनके नेतृत्व की स्पष्टता, साहसिकता और रणनीतिक स्थिरता को दर्शाता है। राजनाथ सिंह ने भारत की सामरिक नीतियों को केवल आक्रामकता ही नहीं दी, बल्कि संतुलन भी प्रदान किया है। उनका कहना है, ह्लहम शांति के पक्षधर हैं, लेकिन यदि कोई हमें ललकारेगा, तो हम उसे जवाब देना जानते हैं।ह्व यह भावना ही आज के भारत को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित कर रही है। उनकी दूरदर्शिता और राष्ट्रप्रेम ने उन्हें देश के सर्वोच्च नेताओं की श्रेणी में स्थापित किया है। राजनाथ सिंह का व्यक्तित्व विनम्रता, नीतिपरक दृढ़ता और संतुलित संवाद का उदाहरण है। वे विरोधी विचारों का सम्मान करते हैं लेकिन राष्ट्रहित से समझौता नहीं करते। इसी विचारधारा को उन्होंने रक्षा मंत्री बनने के बाद अपनी कार्यशैली में उतारा। बीते वर्षों में भारत जिन आतंकी चुनौतियों का सामना कर रहा है, उसमें राजनाथ सिंह का रुख न केवल स्पष्ट रहा है बल्कि निर्णायक भी। कोई आंख तरेर कर तो देखें! पर ललकार की मुद्रा में वे कठोर जबाव देते हैं।

हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद केंद्र सरकार ने जिस तत्परता और आक्रामकता सेऑपरेशन सिंदूरह्व को अंजाम दिया, वह भारत की बदली हुई सैन्य सोच का प्रतीक है। राजनाथ सिंह ने चीन एवं पाक के दोगलेपन पर यह स्पष्ट किया कि ह्लशांति केवल एक भ्रम है, हमें हर पल युद्ध जैसी तैयारी में रहना होगा।ह्व इस अभियान में भारतीय वायुसेना और नौसेना की संयुक्त कार्रवाई ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त कर यह संदेश दे दिया कि भारत अब केवल प्रतिक्रिया नहीं, प्रति-प्रहार की नीति पर चलेगा। उन्होंने यह भी उजागर किया कि इस बार की कार्रवाई में स्वदेशी हथियारों और ड्रोनों की प्रमुख भूमिका रही, जो उनकीआत्मनिर्भर भारतह्व रक्षा नीति की बड़ी सफलता है। जो नवनिर्माण की रफ्तार एवं नई कड़ी है। रक्षा मंत्री ने गर्व से बताया कि भारतीय सेना अब आयात पर निर्भर नहीं, बल्कि स्वदेशी तकनीक से आतंकवाद को जवाब दे रही है। उनका मानना है कि सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा नहीं है, बल्कि राष्ट्र के आत्मबल और तकनीकी सामर्थ्य को विकसित करना भी है।

कैलिफोर्निया के पटाखा गोदाम में विस्फोट के बाद लगी आग, सात व्यक्ति लापता

सैक्रामेंटो (कैलिफोर्निया)। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत के योलो काउंटी में एक पटाखा गोदाम में हुए विस्फोट के बाद आग लग गई। इस गोदाम में आतिशबाजी की सामग्री और उपकरण रखे हुए थे। देखते ही देखते यह आग लगभग 80 एकड़ में फैल गई। विस्फोट के समय गोदाम में मौजूद रहे लोगों में सात अभी तक लापता हैं।एनबीसी न्यूज चैनल की खबर के अनुसार, यह गोदाम सेक्रामेंटो के उत्तर-पश्चिम में एस्पार्टो क्षेत्र में है। सूचना मिलते ही अग्निशमन दल के जवान शाम करीब 5:50 बजे पहुंचे। तब रुक-रुक कर विस्फोट हो रहे थे और आग की लपटों से कई इमारतें घिरी हुई थीं। एस्पार्टो फायर प्रोटेक्शन डिस्ट्रिक्ट के प्रमुख कर्टिस लॉरेंस ने बताया कि हेलीकॉप्टर से बनाए गए वीडियो में गोदाम में आग लगने से पहले छत से सफेद धुआं निकलता दिखाई दिया। फायर मार्शल के कार्यालय के अनुसार, बुधवार को जोखिम कुछ कम हुआ है। इसलिए निकासी आदेश जारी किए गए हैं। खतरों का आकलन करने के लिए घटनास्थल के आसपास अधिकारियों की टीम मौजूद है। आग लगने के बाद घर छोड़कर भागे निवासियों की वापसी के प्रयास किए जा रहे हैं।एस्पार्टो फायर चीफ लॉरेंस के अनुसार, जांचकर्ताओं का मानना है कि संपत्ति का मालिक पायरोटेक्निक लाइसेंसधारक है। आतिशबाजी कंपनी डेवास्टेटिंग पायरोटेक्निक्स ने बुधवार को अपनी वेबसाइट पर कहा कि प्रबंधन को प्रभावित लोगों की चिंता है। कंपनी जांच में पूरा सहयोग कर रही है।

इंडोनेशिया में बाली के पास नौका डूबी, तीन की मौत, 58 लापता

जकार्ता। इंडोनेशिया के रिसॉर्ट द्वीप बाली के पास एक नौका के डूब जाने से तीन लोगों की मौत हो गई और 58 अन्य लापता हो गए। खोज और बचाव दल लापता यात्रियों की तलाश कर रहा है। दल ने चार लोगों को बचा लिया है। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ की खबर के अनुसार, यह नौका दुर्घटना आधी रात से कुछ पहले हुई। एक वरिष्ठ बचाव अधिकारी ने आज सुबह इसकी पुष्टि की। बाली में खोज और बचाव कार्यालय के प्रमुख आई न्योमन सिदकार्या के अनुसार, यह नौका बाली और पूर्वी जावा प्रांत के बीच समुद्री सीमा पर ऊंची लहरों से टकराकर डूब गई। उन्होंने कहा कि तीन लोगों की मौत हो गई। चार अन्य को जीवित बचा लिया गया। यह नौका पूर्वी जावा के बन्युवांगी रीजेंसी के एक बंदरगाह से रवाना हुई थी। नौका बाली के जेम्ब्राना रीजेंसी के गिलिमनुक गांव के एक बंदरगाह के रास्ते पर थी, अचानक उठी ऊंची लहरों के दौरान पलट गई। खोज और बचाव अभियान चल रहा है। इस अभियान में बाली और पूर्वी जावा दोनों की टीमें शामिल हैं। हादसे के समय नौका पर 53 यात्री और 12 चालक दल के सदस्य सवार थे।

प्रधानमंत्री ओली को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, पिछले कार्यकाल की सभी संवैधानिक नियुक्तियां वैध करार

काठमांडू। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की चार साल पहले की गई 52 संवैधानिक नियुक्तियों को सुप्रीम कोर्ट ने वैध करार देते हुए उन्हें बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने 3-2 के बहुमत से फैसला सुनाया। प्रधानमंत्री ओली के पिछले कार्यकाल में संसद के विघटन के बाद भी देश के सभी महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर नियुक्ति की गई थीं। इसके लिए अध्यादेश लाते हुए संवैधानिक परिषद के बैठकों की नियमावली बदली गई थी। ओली के इस फैसले के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायक करते हुए नियुक्तियों को रद्द करने की मांग की गई थी। चार साल तक सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच में इसकी सुनवाई हुई। करीब 14 घंटे की लगातार बैठक के बाद मध्यरात करीब सवा 12 बजे सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने फैसले में सभी 52 नियुक्तियों को वैध करार दिया। प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, मनोज शर्मा, कुमार चुड़ाल और नहकूल सुवेदी ने फैसला सुनाया। प्रधान न्यायाधीश राउत ने कहा कि उनके सहित एक और जज नहकूल सुवेदी ने इन सभी नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला किया है।

माली में सात शहरों पर आतंकी हमला, तीन भारतीयों का अपहरण, केंद्र सरकार ने चिंता जताई, अल कायदा पर शक

नई दिल्ली/बमाको। अफ्रीकी देश माली में तीन भारतीय नागरिकों को अगवा कर लिया गया है। केंद्र सरकार ने इस पर गहरी चिंता जताई है। केंद्र ने माली सरकार से संपर्क कर तीनों भारतीय नागरिकों की जल्द से जल्द रिहाई सुनिश्चित कराने का आग्रह किया है। भारत के विदेश मंत्रालय की कल देररात जारी विज्ञप्ति में कहा कि यह घटना 01 जुलाई की है। अपहरण का यह वाकया उस समय हुआ जब आतंकवादी समूह अल कायदा से संबद्ध एक जिहादी समूह के आतंकवादियों ने माली के सात प्रमुख शहरों पर एक साथ हमला किया। इसलिए शक की सूई अल कायदा पर ठहर रही है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, माली गणराज्य के कायेस में डायमंड सीमेंट फैक्टरी में कार्यरत तीन भारतीय नागरिकों को अपहृत कर लिया गया है।हथियारबंद हमलावरों के एक समूह ने फैक्टरी परिसर में हमलाकर तीन भारतीय नागरिकों को जबरन बंधक बना लिया।

अमेरिकी संसद ने पास किया ट्रंप का 'वन बिग ब्यूटीफुल बिल'

एजेंसी

वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का महत्वाकांक्षी वन बिग ब्यूटीफुल बिल अब कानून बन जाएगा। रिपब्लिकन बहुमत वाली प्रतिनिधि सभा ने इसे मामूली अंतर से पास कर दिया। इसी के साथ प्रतिनिधि सभा ने कर कटौती को बढ़ाकर और सामाजिक सुरक्षा जाल कार्यक्रमों में कटौती करके राष्ट्रपति ट्रंप के घरेलू एजेंडे को पूरा करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। इस बिल पर दोनों सदनों की मुहर को ट्रंप और उनकी रिपब्लिकन पार्टी के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है। द न्यूयॉर्क टाइम्स और अन्य अमेरिकी अखबारों की खबर के अनुसार, बिल का दोनों सदनों में पास होना ट्रंप और उनकी पार्टी के लिए भले ही तात्कालिक जीत है पर अगले साल होने वाले मध्यावधि चुनाव से पहले इसे बड़ा राजनीतिक जुआ माना जा रहा है। कमजोर रिपब्लिकन सांसदों को निश्चित रूप से लाभ में कटौती करने वाले एजेंडे का समर्थन करने पर तीखे हमलों का सामना करना पड़ेगा।

बताया गया है कि दो रिपब्लिकन को छोड़कर सभी ने विधेयक के पक्ष में मतदान किया और डेमोक्रेट ने समान रूप से विरोध किया। न्यूयॉर्क के डेमोक्रेट प्रतिनिधि हकीम जेफ्रीज ने इस विधेयक को संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों की स्वास्थ्य देखभाल पर एक चौतरफा हमला बताया। जेफ्रीज ने प्रतिनिधि सभा के इतिहास में सबसे लंबा भाषण देकर रिकार्ड बनाया। वह विधेयक पर आठ घंटे 46 मिनट तक बोले। जेफ्रीज ने तड़के 4:53 बजे बोलना शुरू किया और दोपहर 1:38 बजे शांत हुए।

दोनों सदनों से पारित बिग ब्यूटीफुल बिल के नाम से चर्चित इस विधेयक को हस्ताक्षर करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के पास भेज दिया गया। उनके हस्ताक्षर किए जाने के बाद यह विधेयक कानून बन जाएगा। 218-214 मत के मामूली बहुमत से पारित यह विधेयक रिपब्लिकन राष्ट्रपति के लिए खास है। इस विधेयक में सीमा सुरक्षा, सेना और सामूहिक निर्वासन के लिए खर्च बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। यह मेडिकेयर में भारी कटौती करेगा और सरकार के ऋण में खरबों डॉलर जोड़ेगा। कराधान पर संयुक्त समिति ने अनुमान जताया है कि यह विधेयक 10 वर्ष में 36.2-ट्रिलियन डालर ऋण में 3.3 ट्रिलियन डालर और जोड़ देगा। राजस्व में 4.5 ट्रिलियन डॉलर की कमी करेगा और खर्च में 1.2 ट्रिलियन डालर की कटौती करेगा।आर्थिक समीक्षकों का कहना है कि बेशक यह निकट अवधि में अमेरिकी सरकार के ऋण डिफॉल्टर बनने की आशंका को टालता है, लेकिन अमेरिका की दीर्घकालिक ऋण समस्याओं को और बदतर बनाएगा। यह स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों में कटौती करने के साथ हरित ऊर्जा को प्रोत्साहन देने वाली दर्जनों योजनाओं पर पूर्णविराम लगा देगा। यूनाइटेड फूड एंड कमर्शियल वर्कर्स इंटरनेशनल यूनियन के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष मिल्टन जोन्स ने कहा कि यह निराशाजनक है। कांग्रेस ने इस नुकसानदायक, बदसूरत विधेयक को पारित कर दिया है। यह कामकाजी परिवारों की जरूरतों को नजरअंदाज करता है। यह ऐसी कटौतियां करता है जो न केवल क्रूर बल्कि आर्थिक रूप से लापरवाहीपूर्ण हैं।

डोनाल्ड ट्रंप ने इस बिल के दोनों सदनों से पास होने पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि अब लाखों परिवारों को डेथ टैक्स से आजादी मिल गई।अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस बिल से बेहतर तोहफा कोई दूसरा नहीं हो सकता। इस बिल के साथ 2024 में आयोवा के लोगों से किया गया मेरा हर बड़ा वादा पूरा हो गया।

अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने मोंटाना में नाबालिगों की गर्भपात पर पैरेंटल कंसेंट कानून को पुनर्जीवित करने की याचिका खारिज की

एजेंसी

वॉशिंगटन। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने मोंटाना राज्य की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें नाबालिगों के गर्भपात के लिए अभिभावकों की सहमति को अनिवार्य बनाने वाले कानून को फिर से प्रभावी करने की मांग की गई थी। यह कानून 2013 में पारित हुआ था, लेकिन इसे अदालत में चुनौती दी गई और यह कभी लागू नहीं हो सका। पिछले साल मोंटाना में सुप्रीम कोर्ट ने इसे अमान्य घोषित कर दिया था। मोंटाना में मतदाताओं ने हाल ही में राज्य के संविधान में गर्भपात के अधिकार को स्पष्ट रूप से सुरक्षित किया है। राज्य के रिपब्लिकन नेताओं का तर्क था कि यह फैसला माता-पिता के अधिकारों का उल्लंघन करता है। राज्य सरकार की ओर से अदालत में कहा गया, मोंटाना यहां जिन अधिकारों की रक्षा करना चाहता है अपने बच्चे के स्वास्थ्य निर्णयों के बारे में जानने और भाग लेने का अधिकार वह माता-पिता के बुनियादी अधिकारों के केंद्र में आता है।हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामला नहीं सुना, लेकिन दो रूढ़िवादी न्यायाधीश सैमुअल एलिटो और क्लेरेंस थॉमस ने अलग से लिखा कि यह इनकार केवल तकनीकी कानूनी मुद्दों पर आधारित है, न कि राज्य के दावे की अस्वीकृति पर। प्लांड पेरेंटहुड संस्था, जिसने इस कानून का विरोध किया, ने कहा कि मोंटाना सुप्रीम कोर्ट का फैसला बच्चों के अधिकारों और माता-पिता के अधिकारों के बीच संतुलन बनाता है, खासकर उस राज्य में जहां गर्भपात का संवैधानिक अधिकार सुरक्षित है। कानून के अनुसार, 18 वर्ष से कम उम्र की किशोरी को गर्भपात कराने के लिए माता-पिता की लिखित और नोटरी प्रमाणित सहमति जरूरी होती।

हॉलीवुड अभिनेता माइकल मैडसेन का 67 वर्ष की आयु में निधन

एजेंसी

लॉस एंजिल्स। हॉलीवुड अभिनेता माइकल मैडसेन का 67 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से गुरुवार सुबह निधन हो गया। उन्हें मालिबू स्थित उनके घर में बेहोश पाया गया। उन्होंने फिल्म निर्देशक क्वेंटिन टारनटिनो की कई फिल्मों में यादगार अभिनय किया है। उनकी प्रवक्ता लिज रोड्रिगेज ने यह जानकारी दी। सीएनएन की खबर के अनुसार, इस संबंध में बोहेमिया एंटरटेनमेंट के सुसान फेरिस और रॉन स्मिथ और प्रवक्ता लिज रोड्रिगेज ने संयुक्त बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि माइकल मैडसेन हॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित अभिनेताओं में से एक थे। उन्हें बहुत से लोग याद करेंगे। लॉस एंजिल्स शेरिफ डिपार्टमेंट लॉस्ट हिल्स स्टेशन के वॉच कमांडर सार्जेंट क्रिस्टोफर जौरेगुई ने कहा कि सुबह अधिकारी मालिबू में मैडसेन के घर पहुंचे और उन्हें बेहोश पाया। स्थानीय समयानुसार सुबह 8:25 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मैडसेन की कुछ यादगार फिल्मों में रिजर्वायर डॉग्स, वन्स अपॉन

ए टाइम इन हॉलीवुड और किल बिल प्रमुख हैं। किल बिल में उनकी खलनायक की भूमिका को कभी नहीं भुलाया जा सकता। उन्होंने 80 के दशक की शुरुआत में टीवी को अभिनय का माध्यम चुना।1983 में सेंट एल्सवेयर में एक शुरुआती भूमिका ने उन्हें पहली बार अभिनय के मानचित्र पर ला खड़ा किया। इसके कुछ समय बाद वह फिल्मों की दुनिया में चले गए। 1991 में रिडले स्कॉट निर्देशित फिल्म थेल्मा एंड लुईस में अपनी छाप छोड़ी। इसमें उन्होंने लुईस (सुसान सारंडन) के प्रेमी जिमी की भूमिका निभाई। अगले साल उन्होंने टारनटिनो के साथ पहली बार रिजर्वायर डॉग्स में काम किया। हिंसा प्रधान इस फिल्म में मैडसेन ने क्रूर मिस्टर ब्लोंड की भूमिका निभाई। उन्होंने एक्शन फिल्मों में भी हाथ आजमाया। 1994 की वायट इयरप ऐसी ही एक मूवी है। उन्होंने 1997 में डॉनी ब्रास्को, 2002 में जेम्स बॉन्ड फिल्म डाई अदर डे और 2005 की सिन सिटी जैसी हिट फिल्मों में काम किया। मैडसेन की जिन्दगी में कई उतार-चढ़ाव भी आए। पिछले साल उन्हें अपनी पत्नी डीअन्ना मैडसेन के साथ विवाद के बाद घरेलू हिंसा के संदेह में गिरफ्तार किया गया था।

अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप के 4.5 ट्रिलियन डॉलर टैक्स बिल को दी मंजूरी, अब राष्ट्रपति की सहमति बाकी

एजेंसी

वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके दूसरे कार्यकाल की सबसे बड़ी नीति सफलता मिली है। प्रतिनिधि सभा ने उनके 4.5 ट्रिलियन डॉलर के टैक्स ब्रेक्स और खर्च कटौती बिल को 218-214 मतों से पारित कर दिया, जिसके बाद यह विधेयक अब उनके हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। बिल को स्वतंत्रता दिवस से पहले पास करना ट्रंप प्रशासन का लक्ष्य था।

यह बिल 2017 के टैक्स ब्रेक्स को स्थायी बनाता है, जिसमें अब नए प्रावधानों के तहत टिप्स, ओवरटाइम और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 6,000 डॉलर तक की अतिरिक्त कटौती शामिल है। इसके अलावा, 350 बिलियन डॉलर की राष्ट्रीय सुरक्षा निवेश, ट्रंप की डिपोर्टेशन नीति और अमेरिका के ऊपर ÷गोल्डन डोम÷ डिफेंस सिस्टम के विकास में भी यह बिल सहायता करेगा। बिल में 1.2 ट्रिलियन डॉलर की कटौती मेडिकेड और फूड स्टैम्प कार्यक्रमों से की गई है, जिससे बुजुर्गों और कुछ माता-पिताओं पर कार्य अनिवार्यता जैसे नियम लागू होंगे। इसके साथ ही, ग्रीन एनर्जी टैक्स क्रेडिट्स में बड़ी कटौती की गई है।

डेमोक्रेट्स ने बिल का कड़ा विरोध किया, जिसे उन्होंने अमीरों के लिए टैक्स गिफ्ट और गरीबों के लिए सजा बताया। डेमोक्रेट नेता हकीम जेफरीज ने इस बिल के खिलाफ लगातार 8 घंटे 44 मिनट तक भाषण दिया और कहा, यह विधेयक अमेरिकी लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर हमला है। वहीं, ट्रंप समर्थक रिपब्लिकन

इसे एक सुंदर और निर्णायक विधेयक कह रहे हैं। हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने कहा, हम एक ही बिल के जरिए देश को पहले से अधिक मजबूत, सुरक्षित और समृद्ध बना रहे हैं। हालांकि, कांग्रेसनल बजट ऑफिस का अनुमान है कि यह पैकेज आगामी 10 वर्षों में 3.3 ट्रिलियन डॉलर का घाटा बढ़ाएगा और लगभग 1.18 करोड़ अमेरिकी स्वास्थ्य कवरेज से वंचित हो सकते हैं।

पाकिस्तान में चेक महिला पर्वतारोही नंगा पर्वत बेस कैंप के पास खड्ड में गिरी, मौत, शुरू होगा खोज अभियान

एजेंसी

इस्लामाबाद। दुनिया के नौवें सबसे ऊंचे पर्वत नंगा की चढ़ाई के लिए पहुंचे चेक गणराज्य के एक पर्वतारोही की बेस कैंप के पास खड्ड में गिरने से मौत हो गई। यह हादसा हुआ। दुनिया में किलर माउंटेन के नाम से कुख्यात नंगा पर्वत गिलगित-बाल्टिस्तान (जीबी) में है। अधिकारियों के अनुसार, खोज अभियान आज शुरू हो सकता है। डॉन समाचार पत्र की खबर के अनुसार, जीबी मुख्यमंत्री के समन्वयक मोहम्मद कासिम ने बताया कि नंगा पर्वत बेस कैंप में गुरुवार सुबह लगभग चार बजे यह दुखद घटना घटी। इस घटना में चेक गणराज्य की पर्यटक कोलोचावा क्लारा की मौत हो गई। उन्होंने क्लारा की मौत का कारण ऑक्सीजन सिलेंडर विस्फोट बताया। डायमर के अतिरिक्त उपायुक्त निजामुद्दीन कासिम के अनुसार, महिला पर्वतारोही कोलोचावा क्लारा कैंप

वन और कैंप टू के बीच की ऊंचाई से गिरी। वह जिस स्थान पर वह गिरीं उसका पता लगाने के बाद शुक्रवार को खोज अभियान शुरू किया जा सकता है। अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि महिला पर्वतारोही के साथ गई टीम इस हादसे के बाद बेस कैंप लौट आई और क्लारा की मौत की सूचना वहीं से दी। अतिरिक्त उपायुक्त निजामुद्दीन ने साफ किया कि प्रारंभिक सूचना में बताया गया था कि विदेशी महिला की मौत ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से हुई, लेकिन बाद में पुष्टि हुई कि वह एक खड्ड में गिर गई थीं, जो उनकी मौत का कारण बना। कासिम ने कहा कि वह 15 जून से अपनी टीम के साथ चिलास में रह रही थीं और 16 जून को बेस कैंप के लिए रवाना हुई थीं। सभी 17 जून को बोनर बेस कैंप पहुंचे। उन्होंने कहा कि क्लारा की खोज के लिए हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि नंगा पर्वत को किलर माउंटेन उपनाम तब मिला जब 1953 में 30 से अधिक पर्वतारोहियों की इस पर चढ़ने की कोशिश में मौत हो गई थी। नंगा पर्वत की चोटी से सिंधु नदी बिलकुल साफ दिखती है। सिंधु नदी नंगा पर्वत के उत्तरी भाग से घूमकर दक्षिण-पश्चिम में पाकिस्तान के बीच से गुजरती है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिन-का-बाब जलधारा को माना जाता है।

प्रधानमंत्री शहबाज के मानहानि केस का सामना कर रहे इमरान खान पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

एजेंसी

इस्लामाबाद। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के मानहानिक केस का सामना कर रहे और लंबे समय से जेल में बंद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अपदस्थ प्रधानमंत्री इमरान खान ने मामले की सुनवाई करने वाली अदालत के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के अनुसार, याचिका में पीटीआई संस्थापक ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि जब तक उनकी अपील पर कोई फैसला नहीं आ जाता, तब तक मानहानि मामले में कार्यवाही स्थगित कर दी जाए। उनका तर्क है कि कानून के तहत केवल जिला और सत्र न्यायालय को ही ऐसे मानहानि के मामलों की सुनवाई करने का अधिकार है। याचिका में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र को भी चुनौती दी गई है, जिनके फैसले को पहले लाहौर हाई कोर्ट ने बरकरार रखा था। खान की कानूनी टीम ने सुप्रीम कोर्ट से अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और लाहौर हाई कोर्ट दोनों के आदेशों को रद्द करने की मांग की है। इसके अलावा, याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अपील पर निर्णय होने तक मामले में आगे की कार्यवाही को रोकने का आग्रह किया गया है। साल 2017 में शहबाज शरीफ ने तत्कालीन विपक्षी नेता इमरान खान के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। खान पर प्रतिष्ठा और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले बयान देने का आरोप लगाया गया था। मुकदमे के अनुसार, ये निराधार और दुर्भावनापूर्ण बयान मीडिया में व्यापक रूप से प्रसारित किए गए। इससे शरीफ की सार्वजनिक छवि खराब हुई। उन्हें अत्यधिक मानसिक यातना, पीड़ा और चिंता के दौर से गुजरना पड़ा।

13वें वर्ल्ड पीस फोरम में वैश्विक सुरक्षा पर गहन मंथन

एजेंसी

बीजिंग। चीन की राजधानी बीजिंग में आयोजित 13वें वर्ल्ड पीस फोरम में 86 देशों और क्षेत्रों के 1,200 से अधिक विशेषज्ञ, नीति निर्माता और पूर्व राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए। फोरम का इस बार का थीम वैश्विक शांति और समृद्धि को आगे बढ़ाना- साझा जिम्मेदारी, लाभ और उपलब्धि है। फोरम का उद्घाटन करते हुए त्सिंगहुआ विश्वविद्यालय के अध्यक्ष और वर्ल्ड पीस फोरम के चेयरमैन ली लुमिंग ने कहा कि वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में अस्थिरता और बढ़ते क्षेत्रीय संघर्षों के कारण विश्व शांति और विकास अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे समय में वैश्विक एकता और संवाद को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है। फोरम के प्रमुख वक्ताओं में

शामिल जापान के पूर्व प्रधानमंत्री युकियो हातोयामा ने कहा कि ÷शांति हथियारों से नहीं, संवाद से हासिल की जा सकती है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि जापान को अमेरिका से अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता मजबूत करते हुए चीन और कोरिया के साथ त्रिपक्षीय सहयोग बढ़ाना चाहिए। हातोयामा ने ताइवान मुद्दे को चीन का आंतरिक मामला बताया और जापान से आग्रह किया कि वह ताइवान की स्वतंत्रता के समर्थन से स्पष्ट रूप से दूरी बनाए ताकि क्षेत्रीय तनाव को कम किया जा सके।

फोरम में कुल चार मुख्य सत्र और 18 पैनल चर्चाएं आयोजित होंगे, जिनमें अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, वैश्विक सुरक्षा संकट, ग्लोबल साउथ की भूमिका और महाशक्तियों के बीच समन्वय जैसे विषयों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। यह फोरम 2012 से त्सिंगहुआ विश्वविद्यालय और चीनी जन विदेश मामलों की संस्था द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य नीति विशेषज्ञों और वैश्विक थिंक टैंकों के लिए संवाद का एक प्रभावी मंच प्रदान करना है।

यूक्रेन युद्ध पर पीछे नहीं हटेगा रूस, ट्रंप से फोन पर बातचीत में पुतिन का दो टूक बयान

एजेंसी

मॉस्को। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच एक महत्वपूर्ण टेलीफोन वार्ता हुई, जिसमें दोनों नेताओं ने ईरान, यूक्रेन और अन्य अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। हालांकि पुतिन ने ट्रंप से बातचीत के दौरान स्पष्ट किया कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अपने मूल उद्देश्यों से पीछे नहीं हटेगा। यह इस वर्ष ट्रंप के व्हाइट हाउस लौटने के बाद दोनों नेताओं की छठी सार्वजनिक रूप से पुष्टि की गई बातचीत थी। इस बातचीत को लेकर क्रेमलिन के वरिष्ठ सलाहकार यूरी उशाकोव ने बताया कि हमारे राष्ट्रपति ने स्पष्ट किया कि रूस उन कारणों को खत्म करने के अपने लक्ष्य में अडिग है, जिन्होंने मौजूदा टकराव को जन्म दिया है, और वह इन लक्ष्यों से पीछे नहीं हटेगा। हालांकि, पुतिन ने यह भी संकेत दिया कि रूस यूक्रेन के साथ बातचीत से समाधान निकालने के लिए

तैयार है। इस विस्तृत वार्ता में ईरान और पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा हुई। ट्रंप ने एक बार फिर युद्ध को शीघ्र समाप्त करने की आवश्यकता पर बल दिया। जबकि पुतिन ने कहा कि सभी विवादों को केवल राजनीतिक और कूटनीतिक तरीकों से सुलझाया जाना चाहिए।यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप ने शीघ्र संघर्षविराम की आवश्यकता पर जोर दिया, जबकि पुतिन ने कहा कि रूस कीव के साथ वार्ता को लेकर तैयार है, लेकिन साथ ही यह भी दोहराया कि मॉस्को अपने ÷रणनीतिक लक्ष्य÷ प्राप्त करने और संघर्ष के ÷मूल कारणों÷ को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।पुतिन ने यह भी दोहराया कि शांति समझौते की कोई भी संभावना यूक्रेन द्वारा नाटो में शामिल होने की योजना छोड़ने और रूस द्वारा कब्जाए गए क्षेत्रों को मान्यता देने पर ही आधारित हो सकती है, जिसे कीव और उसके पश्चिमी सहयोगी सिरे से खारिज करते रहे हैं। इस बातचीत की पृष्ठभूमि में पेंटागन द्वारा यूक्रेन को हथियारों की कुछ खेपों को अस्थायी रूप से रोकने की पुष्टि हुई है। इनमें एयर डिफेंस मिसाइल और प्रिसिशन गाइडेड आर्टिलरी जैसे अहम हथियार शामिल हैं।

ईरान की सेना इजराइली आक्रमण का मुकाबला करने के लिए तैयार

एजेंसी

तेहरान। ईरान ने कहा है कि उसकी सेना इजराइल के किसी भी आक्रमण का मुकाबला करने के लिए तैयार है। ईरान अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा। विदेशमंत्री अब्बास अराघची ने अपने वेनेजुएला के समकक्ष इवान गिल पिंटो को फोन पर बातचीत में अपने रुख से अवगत कराया।

ईरान सरकार के इस्लामिक डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन की न्यूज एजेंसी मेहर की खबर के अनुसार, अराघची ने इवान गिल पिंटो से ईरान के खिलाफ इजराइली शासन और अमेरिका के सैन्य आक्रमण के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र के नए घटनाक्रम पर चर्चा की।

शीर्ष ईरानी राजनयिक ने इजराइल और अमेरिकी सैन्य आक्रमण की निंदा करने के लिए वेनेजुएला प्रशासन का आभार व्यक्त किया। अराघची ने कहा कि अमेरिका और इजराइल ने आक्रमण में संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों और नियमों का उल्लंघन किया है।वेनेजुएला के विदेशमंत्री ने इस बातचीत में इस्लामी क्रांति के नेता अयातुल्ला सैय्यद अली खामेनेई, ईरान सरकार और लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि एक मित्र देश के रूप में वेनेजुएला हमेशा इस्लामी गणराज्य ईरान के साथ खड़ा रहेगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक शासन प्रणाली में प्रभावी सुधारों की आवश्यकता पर दिया जोर

एजेंसी

अक्रा (घाना)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को अफ्रीकी देश घाना की लोकतांत्रिक आदर्शों एवं समावेशी प्रगति के प्रति प्रतिबद्धता को पूरे अफ्रीकी महाद्वीप के लिए प्रेरणा का स्रोत बताया और जलवायु परिवर्तन, महामारी, आतंकवाद और साइबर सुरक्षा जैसे नए और जटिल संकटों का सामना कर रही दुनिया को बचाने के लिए वैश्विक शासन प्रणाली में विश्वसनीय और प्रभावी सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। श्री मोदी ने आज घाना की संसद के एक विशेष सत्र को संबोधित किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। संसद अध्यक्ष अल्बान किंग्सफोर्ड सुमाना बागबिन द्वारा आयोजित इस सत्र में संसद सदस्यों, सरकारी अधिकारियों और दोनों देशों के विशिष्ट मेहमानों ने भाग लिया। उन्होंने माना कि यह संबोधन भारत-घाना संबंधों में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित करता है, जो दोनों देशों को एकजुट करने वाले आपसी सम्मान और साझा लोकतांत्रिक मूल्यों को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में स्वतंत्रता के लिए साझा संघर्षों और लोकतंत्र और समावेशी विकास के प्रति एक समान प्रतिबद्धता के माध्यम से बनाए गए भारत और घाना के बीच ऐतिहासिक बंधनों पर प्रकाश डाला। उन्होंने घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रामणि महामा और घाना के लोगों के प्रति उन्हें प्रदान किए गए राष्ट्रीय सम्मान के लिए आभार व्यक्त किया और इसे स्थायी मित्रता का प्रतीक बताया। घाना के महान नेता डॉ. क्वामे नक्रुमाह के योगदान का उल्लेख करते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि एकता, शांति और न्याय के आदर्श मजबूत और स्थायी साझेदारी की नींव हैं। डॉ. नक्रुमा को उद्धृत करते हुए, जिन्होंने एक बार कहा था- जो ताकतें हमें एकजुट करती हैं वे आंतरिक हैं और अधिरोपित प्रभावों से अधिक हैं जो

हमें अलग रखती हैं और जिन्होंने लोकतांत्रिक संस्थानों के निर्माण के दीर्घकालिक प्रभाव पर बहुत जोर दिया, प्रधानमंत्री ने लोकतांत्रिक मूल्यों के पोषण के महत्व को रेखांकित किया। यह देखते हुए कि भारत ने लोकतंत्र की जननी के रूप में लोकतांत्रिक लोकाचार को अपनी संस्कृति के हिस्से के रूप में अपनाया है, प्रधानमंत्री ने भारत में लोकतंत्र की गहरी और जीवंत जड़ों पर प्रकाश डाला। उन्होंने विविधता में एकता की शक्ति के प्रमाण के रूप में भारत की विविधता और लोकतांत्रिक शक्ति की ओर इशारा किया, जो घाना की अपनी लोकतांत्रिक यात्रा में प्रतिध्वनित मूल्य था। उन्होंने जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, महामारी और साइबर खतरों जैसी महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला और वैश्विक शासन में एक सामूहिक वैश्विक दक्षिण आवाज का आह्वान किया। इस संदर्भ में उन्होंने भारत की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को जी-20 के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने को रेखांकित किया।

न्यूज फ्लैश

जेबीटी के 19 पदों के लिए काउंसलिंग 21, 22 व 23 जुलाई को

दिव्य दिल्ली-अमरप्रीत सिंह (सोलन)

कनिष्ठ बुनियादी अध्यापकों (जे.बी.टी.) के भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों की श्रेणी के अंतर्गत 19 पदों पर भर्ती की जानी है। यह जानकारी उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा सोलन मोहिंदर चंद ने दी। मोहिंदर चंद ने कहा कि इन पदों पर भर्ती के लिए काउंसलिंग 21, 22 तथा 23 जुलाई, 2025 को उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा सोलन के कार्यालय में प्रातः 10.30 बजे से आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि 21 जुलाई, 2025 को कांगड़ा, चम्बा, लाहौल-स्पीति तथा कुल्लू जिलों के उम्मीदवारों के लिए, 22 जुलाई, 2025 को हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना तथा किन्नौर जिलों के उम्मीदवारों के लिए तथा 23 जुलाई, 2025 को सोलन, मण्डी, शिमला, सिरमौर एवं सभी जिलों के बचे हुए उम्मीदवारों के लिए काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि चयन प्रक्रिया में वहीं उम्मीदवार भाग ले सकते हैं जो भर्ती एवं पदोन्नति (2024) नियमों के तहत निर्धारित योग्यता व श्रेणीवार बैच की शर्त पूर्ण करते हों। उन्होंने कहा कि सामान्य वर्ग के 12 पदों के लिए 31 दिसम्बर, 2018 तक, अनुसूचित जाति के एक पद के लिए 31 दिसम्बर, 2020 तक, अनुसूचित जनजाति श्रेणी के 03 पदों के लिए 31 दिसम्बर, 2019 तक तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के 03 पदों के लिए 31 दिसम्बर, 2018 तक के बैच काउंसलिंग के लिए बुलाए गए हैं। उप निदेशक ने कहा कि काउंसलिंग में उम्मीदवार 10वीं तथा 12वीं कक्षा का योग्यता प्रमाण पत्र, व्यावसायिक योग्यता या इसके समकक्ष प्रमाण पत्र, शिक्षक योग्यता परीक्षा जेबीटी (टेट) प्रमाण पत्र, अन्य उच्च योग्यता प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हिमाचली प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का पंजीकरण पत्र, सैनिक कल्याण के सम्बन्धित उप निदेशक द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक के आश्रित का प्रमाण पत्र, सैनिक कल्याण के सम्बन्धित उप निदेशक द्वारा जारी नॉन-रिहेबीलीटेटिड सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज बुक की छायाप्रति, नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो तथा उपमण्डलाधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी शपथ पत्र साथ लाना होगा।

युवक को साढे चार ग्राम चिट्टे सहित पकड कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया

दिव्य दिल्ली : रंधावा (पठानकोट)

पंजाब सरकार व पंजाब पुलिस की ओर से युद्ध नशों के विरूद्ध छेडी गई मुहिम के तहत , जिला पुलिस प्रमुख डीएस ढिल्लों की हिदायत अनुसार, नशों पर नकेल कसने के लिए शाहपुर कंडी पुलिस ने शाहपुर कंडी की खंडहर हो चुकी कालोनी के समीप से एक युवक से साढे चार ग्राम चिट्टा पकडने में सफतला हासिल की है। शाहपुर कंडी पुलिस स्टेशन की एसएचओ सब इंस्पैक्टर अमनप्रीत कौर अनुसार, उनकी पुलिस स्टेशन के एएसआई राकेश कुमार, गत सांयकाल यू वन की खंडहर हो रही कालोनी के समीप से गश्त कर रहे थे तो उस समय एक युवक अपनी बाईक सहित , उक्त खंडहर हो चुकी कालोनी के आवासों के बाहर खडा था तथा जैसे ही उक्त युवक ने पुलिस को देखा तो अपनी जेब में से एक पारदर्शी प्लास्टिक का लिफाफा निकाल कर साथ लगती झाडियों में फैंक दिया, जिसको पुलिस पार्टी ने देख लिया । पुलिस ने बताया कि शक होने पर उनकी पुलिस के एएसआई राकेश कुमार अपनी पुलिस पार्टी के साथ उक्त युवक के पास पहुंची तो , उक्त फैंकें गए प्लास्टिक के लिफाफे के बारे पूछने ली, जिसपर पुलिस पार्टी ने उक्त पारदर्शी प्लास्टिक के लिफाफे को उसी समय साथ लगती झाडियों में से पकड कर पूछा, जिसपर वह कोई जबाव नहीं दे सका।

भारी पुलिस दलबल के साथ उठायाॅ नगरोटा सूरियां विकासखंड कार्यालय का सामान

प्रेम स्वरूप शर्मा (नगरोटा सूरियां)

नगरोटा सूरियां विकासखंड कार्यालय को आखिर आज पुलिस दलबल के साथ जवाली के लिए स्थानांतर कर के ले गई संघर्ष समिति की तरफ से जब कार्यालय की फाइलें तथा फर्नीचर इत्यादि पुलिस दलबल के साथ उठाया जा रहा था तब महिलाओं ने इसका कड़ा विरोध भी किया तथा धरने पर बैठ गई लेकिन पुलिसनले दलबल के साथ उन्हें वहा उठाया और गाड़ियों में सामान रखा पुलिस की दो बटालियन तथा भारी संख्या में महिला पुलिस यहां पर पहुंची हुई थी संघर्ष समिति ने सुबह खंडविकास अधिकारी तहसीलदार व डीएसपी महोदय को एक ज्ञापन सोपा की महोदय हमने हाईकोर्ट में इसकी रिट पिटिशन की है और 11:00 बजे उसकी सुनवाई रखी है उसके फैसले के बाद आप यहां से सामान उठा कर ले जा सकते हैं हम विरोध नहीं करेंगे लेकिन खंड विकास अधिकारी ने एक नहीं सुनी और खंड विकास कार्यालय का रखा सामान उठाने के आदेश दे दिए काफी देर तक वहां पर चंद्र कुमार व सरकार के विरुद्ध जमकर नारे बाजी हुई और कहा कि इसका जवाब हम हम चंद्र कुमार को चुनाव में देगे भारी सख्या में महिलाएं इस आंदोलन में पहुंची हुई थी 80 से 85 वर्ष तक की महिलाएं भी इस आंदोलन में पहुंची हुई थीएक बार तो पुलिस के साथ काफी धक्का मुक्की भी जनता और महिलाओं के साथ सामान को ले जा रहे थे पुलिस केसथ हुई महिलाओं ने गेट पर धरना दे दिया और कहा कि हमें गिरफ्तार करो हम सामान को नहीं ले जाने देंगे हमारा यह 50 वर्ष का पुराना खंड विकास कार्यालय है लेकिन पुलिस किसी की नहींसुन रही थी पत्रकारों ने खंड विकास अधिकारी से पूछा कि कार्यालय कितने बजे खुलता है तो उन्होंने कहा कि 10:00बजे लेकिन खंड विकास अधिकारी सुबह 8:00 बजे ही पुलिस दलबल के साथ आप यहां पहुंच गएथे इस पर और विकास अधिकारी कोई जवाब नहीं दे सकेजबकि संघर्ष समिति को किसी प्रकारकी कोई जानकारी खंड विकास कार्यालय द्वारा समितिको नहीं दी गई थी बाद में समिति द्वारा एक विशाल रैली भी निकाल गई तथा बस अड्डे पर एक विशाल जन सभा भी हुई जिसमें महिलाओं ने कहा कि आज का दिन काले अक्षर में लिखा जाएगा तथा स्थानीय विधायक कृषि चंद्र कुमार का नाम भी यहां की जनता काले अक्षरों में लिखेगी तथा इस अवसर पर महिलाओं ने कहा चंद्र कुमारको क्षेत्र में आने नहीं देंगे इस अवसर पर भाजपा नेता संजय गुलेरिया ब्लाक समिति के अध्यक्ष धीरज अत्री पूर्वउपाध्यक्ष बालवीर पठानिया संघर्ष समितिके अध्यक्ष संजय महाजन प्रधान जीएस बेदी समाज।

विकास और पर्यावरण का संतुलन हमारी प्राथमिकता

दिव्य दिल्ली- हरोली पोलिया (ऊना)

ऊना जिले के हरोली विकास खंड में निमार्णाधीन बल्क ड्रग पार्क परियोजना को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों और भ्रांतियों के निराकरण के लिए जिला प्रशासन ने मंगलवार को एक महत्त्वपूर्ण पहल करते हुए परियोजना स्थल पोलियां में ह्यमीडिया वॉकथ्रूह्ल आयोजित किया। उपायुक्त जतिन लाल की अगुवाई में आयोजित इस मीडिया वॉकथ्रू में पत्रकारों को साइट पर ले जाकर परियोजना के विभिन्न पहलुओं की ब्रीफिंग दी गई और पर्यावरणीय, तकनीकी व सामाजिक तथ्यों से अवगत कराया गया। इस अवसर पर उद्योग विभाग के संयुक्त निदेशक अंशुल धीमान, डीएफओ सुनील राणा सहित अन्य अधिकारी भी उपायुक्त के साथ रहे और उन्होंने अपने विभागों से जुड़ी जानकारियां साझा की।उपायुक्त ने कहा कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर परियोजना को लेकर भ्रांतियां फैला रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि यह परियोजना राज्य के औद्योगिक भविष्य के लिए निर्णायक है और इसे वैज्ञानिक एवं पर्यावरणीय संतुलन के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है।उन्होंने कहा कि परियोजना निर्माण में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्र व राज्य सरकार की पर्यावरणीय गाइडलाइनों का कठोर अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रशासन प्रत्येक आयाम की सूक्ष्मता से समीक्षा कर रहा है ताकि पारदर्शिता बनी रहे और जनविश्वास मजबूत हो।

बीएलओज की तीसरे दिन के प्रशिक्षण में कई महत्वपूर्ण टिप्स दिए गए

दिव्य दिल्ली : रंधावा (पठानकोट)

भारतीय चुनाव आयोग दिल्ली व व पंजाब चुनाव चुनाव के मुख्य चुनाव अधिकारी की हिदायत अनुसार, जिला चुनाव अधिकारी कम जिलाधीश आदित्य उप्पल आईएएस की दिशानिदेर्शानुसार शाहपुर कंडी के माडल सीसे स्कूल में बीएलओज व अन्य चुनावों में लगे हुए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए वर्कशाप का आयोजन किया गया। । इस प्रशिक्षण वर्कशाप जिला चुनाव पंजीकरण अधिकारी कम एसडीएम धार कलां मेजर डा. सुमित मुध के नेतृत्व में आयोजित चुनावों में लगे हुए कर्मचारियों को तीसरे दिन भी प्रशिक्षण जारी रहा। जिला चुनाव पंजीकरण अधिकारी कम एसडीएम धार कलां मेजर डा. सुमित मुध के नेतृत्व में आयोजित प्रशिक्षण वर्कशाम में विस क्षेत्र सुजानपुर के सौ से से ले कर ढेड सौ बूथ नंबर तक के बीएलओज व सैक्टर अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। । इस प्रशिक्षण वर्कशाप में मास्टर ट्रेनर एसडीओ सूरज कुमार, एसडीओ गुरविंदर सिंह, मुनीष महाजन लेक्चर, महिंद्र पाल, चुनाव इंचार्ज सुमेश शर्मा व अन्य अधिकारियों की ओर से आए हुए बीएलओज को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में विशेष नाटक व अन्य महत्वपूर्ण टिप्स पेश करके, मत की महत्वता पर प्रकाश डाला गया।

आपदा की पीड़ा भुलाकर सुक्खू सरकार ने मित्रों पर लुटाया जनता का खून-पसीना: गोविंद सिंह

दिव्य दिल्ली-मनीष ठाकुर

भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश इस समय भीषण प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं, अनेक परिवारों के चूल्हे बुझ गए हैं और हजारों लोग खाद्य सामग्री व अन्य मूलभूत आवश्यकताओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। परंतु इस कठिन समय में प्रदेश सरकार का ध्यान जनता के दर्द को समझने और राहत पहुंचाने के बजाय अपने राजनीतिक मित्रों की जेबें भरने पर है। गोविंद सिंह ठाकुर ने जारी बयान में कहा कि सुक्खू सरकार ने विभिन्न निगमों और बोर्डों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों के भत्ते में 30 हजार रुपये से सीधा 80 हजार रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी कर दी है। यह फैसला स्पष्ट करता है कि सरकार को आपदा से पीड़ित जनता की नहीं, बल्कि उन लोगों की चिंता है जो चुनाव में पंच और प्रधान तक नहीं बन सकते है उन्हीं पर आपदा की इस घड़ी में सुक्खू सरकार मेहरबान हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि आपदा राहत के नाम पर प्रदेश सरकार द्वारा महज दिखावा किया जा रहा है। राहत के लिए भारत सरकार द्वारा दी जा रही सहायता का भी बदले की राजनीति की भावना से दुरुपयोग किया जा रहा है। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि कुल्लू जिले के सैकड़ों युवाओं को पिछले 9 महीनों से कौशल विकास योजना के तहत मिलने वाली राशि का भुगतान नहीं हुआ है। प्रदेश के लगभग 25 लाख युवा इस पैसे का इंतजार कर रहे हैं वहीं हिमाचल पथ परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन, मेडिकल बिल और अन्य भत्तों का भुगतान भी नहीं हो रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण ऐसे समय में अपने चहेतों को तोहफे देना और उनके मानदेय में भारी बढ़ोतरी करना सुक्खू सरकार की संवेदनशीलता और जनविरोधी सोच को उजागर करता है।

आईडिया ऑफ भारत फाउंडेशन का प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मिला

दिव्य दिल्ली : विनय महाजन (नूरपुर)

नूरपुर आईडिया ऑफ भारत फाउंडेशन के प्रतिनिधि मंडल ने राजभवन शिमला में महामहिम राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ला जी से भेंट की। इस अवसर पर फाउंडेशन द्वारा चलाए गए नशा विरोधी अभियान की जानकारी राज्यपाल को दी गई। प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें अभियान की विस्तृत रिपोर्ट और एक ज्ञापन भी सौंपा।प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व फाउंडेशन के अध्यक्ष राहुल शर्मा ने किया। उन्होंने राज्यपाल महोदय को अवगत कराया कि फाउंडेशन द्वारा मई और जून में हिमाचल प्रदेश के नूरपुर क्षेत्र सहित अन्य ग्रामीण इलाकों में नशा मुक्त भारत के उद्देश्य से एक सघन जनजागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें युवाओं, अभिभावकों और ग्राम पंचायतों की भागीदारी सुनिश्चित की गई।राज्यपाल महोदय ने अभियान की सराहना करते हुए समाज के लिए इसे एक सराहनीय पहल बताया। उन्होंने इस दिशा में और प्रभावी कार्य योजना बनाने के लिए कुछ सुझाव भी दिए और भविष्य में इस अभियान को और व्यापक रूप से लागू करने हेतु संभव सहयोग का आश्वासन भी दिया।आईडिया ऑफ भारत फाउंडेशन समाज के विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता और समाधान की दिशा में कार्यरत है, और आगे भी प्रदेश को नशा मुक्त बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास करता रहेगा।इस प्रतिनिधि मंडल में कैप्टन दलेर सिंह पठानिया, प्रेम शर्मा एवं एडवोकेट जनक राज सम्मिलित रहे।

भडोली में बिजली चोरी करने पर पकड़े गए, 1.33 लाख का जुर्माना लगाया

दिव्य दिल्ली-पंकज शर्मा (कांगड़ा)

कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी के साथ लगते भडोली में विद्युत उपमंडल क्षेत्रों में बिजली चोरी और अनधिकृत बिजली उपयोग के मामलों का खुलासा हुआ है। बिजली बोर्ड की टीमों ने एक स्थान पर छापेमारी कर यह कार्रवाई की है। इस मामले में कुल ?1,33,444 का जुमार्ना आरोपित किया गया है। भडोली डिवीजन के तहत यह कार्रवाई अमल में लाई गई है। बताया जा रहा है कि घर और दुकान में बिजली की ह्यकुंडीह्ल लगाई हुई थी और उसके द्वारा बिजली चोरी की जा रही थी।एक्सईएन कर्णवीर सिंह पटियाल ने बताया कि बिजली बोर्ड बिजली चोरी और अवैध उपयोग पर कड़ी निगरानी बनाए हुए है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि वे बिजली का दुरुपयोग न करें और विभागीय नियमों का पालन करें। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में किसी को भी अनाधिकृत बिजली उपयोग या चोरी करते पकड़ा गया, तो नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता पुन्नू राम की एक भेंट वार्ता

दिव्य दिल्ली : विनय महाजन (नूरपुर)

नूरपुर विधानसभा क्षेत्र खजिया के निवासी भाजपा के सीनियर कार्यकर्ता व बीजेपी प्रकोष्ठ सेंट के पूर्व अध्यक्ष व हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड यूनियन के पूर्व उपाध्यक्ष पुन्नू राम,(83) जिन्होंने अपना जीवन भाजपा के लिए अर्पित किया है बिना किसी मोह के' उन्होंने एक भेट वार्ता में कहा कि भाजपा हाई कमान ने 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रणवीर सिंह निक्का को टिकट देकर जो निर्णय लिया उसका हमने कभी भी इस मामले में सोचा भी नही था कि केंद्रीय भाजपा हाई कमान द्वारा बीजेपी प्रत्याशी के लिए ऐसा निर्णय लिया जा सकता था।

2 किलो 84 ग्राम चरस सहित दो तस्कर गिरफ्तार

दिव्य दिल्ली : विनय महाजन (नूरपुर)

जिला पुलिस नूरपुर द्वारा नशे के विरुद्ध चलाये गये अभियान के आज नशा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्यवाही अमल में लाते हुये पुलिस थाना ज्वाली के अधीन मुकाम 32 मील में गौरव होटल के बाहर गश्त के दौरान एक सिल्वर रंग की गाड़ी (ढइ08-उउ-4977) में सवार विनय कुमार पुत्र श्री सागर, निवासी वार्ड नं. 05, नूरपुर, जिला कांगड़ा (उम्र 32 वर्ष) व किशोरी लाल पुत्र श्री तीर्थ राम, निवासी गांव सियोली, डा. पनियार, तहसील बंजार, जिला कुल्लू (उम्र 20 वर्ष) के कब्जे से 2 किलो 84 ग्राम चरस बरामद करने मे सफलता प्राप्त की है। जिस पर उपरोक्त दोनो आरोपीयो के विरुद्ध अभियोग संख्या 89 / 25 दिनांक 09.07.25 अधीन धारा 20,25एन डी एन्ड पी एस एक्ट के अधीन दर्ज करके आरोपियो की गिरफ्तार किया गया है ' यह जानकारी एक प्रेस विज्ञाप्ति में जिला पुलिस अध्यक्ष अशोक रत्न नूरपुर ने देते हुए बताया कि इस अभियोग मे नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस जिला नुरपूर द्वारा नशे के खिलाफ चलाये गये अभियान के अन्तर्गत साल 2025 मे एन डी एन्ड पी एस एक्ट के अधीन 41 अभियोग दर्ज किये गये। जो उपरोक्त अभियोगो मे कुल 789.69 ग्राम चिट्टा, व 14 किलो 178 ग्रांम चरस बरामद की गई है। इसके साथ ही तक वितिय जाँच के दौरान आरोपियो की कुल 18,70,04,257/- रुपये की चल व अचल सम्पति को जब्त किया जा चुका है। इसके ड्डअलावा अन्य दर्ज कई अभियोगो मे भी आरोपियो की चल व अचल सम्पति की जाँच अमल में लाई जा रही है। वर्ष 2025 के दौरान अवैध नशे के कारोबार मे शामिल 72 लोगो को जिनमे 61 पुरुष व 11 महिलाये शामिल है को गिरफ्तार किया गया है।

बीएलओ की बैठक व चुनाव संबंधी प्रशिक्षण दिया गया

दिव्य दिल्ली : कमल रंधावा (पठानकोट)

भारतीय चुनाव आयोग दिल्ली व व पंजाब चुनाव चुनाव के मुख्य चुनाव अधिकारी की हिदायत अनुसार, जिला चुनाव अधिकारी कम जिलाधीश आदित्य उप्पल आईएएस की दिशानिदेर्शानुसार शाहपुर कंडी के माडल सीसे स्कूल में बीएलओज व अन्य चुनावों में लगे हुए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए वर्कशाप का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण वर्कशाप जिला चुनाव पंजीकरण अधिकारी कम एसडीएम धार कलां मेजर डा. सुमित मुध के नेतृत्व में आयोजित की गई। इस प्रशिक्षण वर्कशाप में मास्टर ट्रेनर ट्रेनर एसडीओ सूरज कुमार, एसडीओ गुरविंदर सिंह, मुनीष महाजन लेक्चर, महिंद्र पाल व अन्य अधिकारियों की ओर से आए हुए बीएलओ को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में विशेष नाटक पेश करके, मत की महत्वता पर प्रकाश डाला गया तथा मतदाताओं को अपने मत का सदुपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। प्रशिक्षण में बताया कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदाताओं को जागरूक करना जरूरी है। चुनाव इंजार्च सुमेश शर्मा ने आए हुए विस क्षेत्र सुजानपुर के पचास से ले कर सौ बूथ तक के बीएलओ व सेक्टर अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर चुनाव इंचार्ज सुमेश शर्मा, अमरदीप सिंह, सुभाष भट्ट, देवेंद्र अत्री , अमन व अन्य उपस्थित थे।

गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने अमल में लाई कारवाई

दिव्य दिल्ली- पंकज शर्मा (ज्वालामुखी)

ज्वालामुखी पुलिस ने 139 ग्राम चरस के साथ 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया है। पुलिस द्वारा पकड़े गए व्यक्तियों की पहचान सुरेन्द्र कुमार पुत्र लज्जाराम निवासी खराबान तहसील पदर जिला मंडी व शरीफ दीन पुत्र करम दीन निवासी सलिहार खुंडियां के रूप में हुई है। बहरहाल इस संबंध में पुलिस द्वारा एन डी पी एस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। आरोपियों को पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश करने के बाद यहां नियमानुसार कारवाई अमल में लाई जाएगी। मामले की पुष्टि एस पी देहरा मयंक चौधरी ने की है।जानकारी के अनुसार बीती रात ज्वालामुखी पुलिस ने डी एस पी आर पी जायसवाल के नेतृत्व में थाना प्रभारी विजय कुमार व उनकी पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कारवाई अमल में लाई है। इस दौरान पुलिस ने सु रोड़ पर टेडा मंदिर के पास आरोपियों से 139 ग्राम चरस बरामद की। बहरहाल पुलिस की मामले को लेकर छानबीन जारी है।

उक्त व्यक्तियों ने चरस कहां से खरीदी और आगे वह इसे किसे बचने वाला था पुलिस उसके सभी पहलुओं को खंगाल रही है। वहीं पुलिस नशे के सौदागरों तक पहुंचने के लिए इनके मोबाइल फोन का रिकॉर्ड भी खंगालेगी।

जैकलीन फर्नांडिस

को 200 करोड़ के मनी लॉन्डरिंग केस में राहत नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका

बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की मुश्किलें मनी लॉन्डरिंग केस में कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. उन्हें सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के मनी लॉन्डरिंग केस में राहत नहीं मिल पा रही है. मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में श्वष्ठ की ओर से दर्ज स्नड्ढक्रऔर चार्जशीट को जैकलीन ने चुनौती दी थी और इस केस को बंद करने की मांग की थी. मगर जैकलीन की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.ईडी ने सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ की लॉन्ड्रिंग के मामले में जैकलीन को आरोपी बनाया है. ED ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि सुकेश चंद्रशेखर के आपराधिक अतीत की जानकारी होने के बावजूद जैकलीन उससे महंगे गिफ्ट आभूषण वगैरह ले रही थीं. इस मामले में जैकलीन को पूछताछ के लिए भी बुलाया जा चुका है. लेकिन एक्ट्रेस का ऐसा मानना है कि उन्हें इस मामले में गलत फंसाया जा रहा है और उनका सुकेश चंद्रशेखर के साथ भी कोई रिलेशन कभी नहीं रहा है.

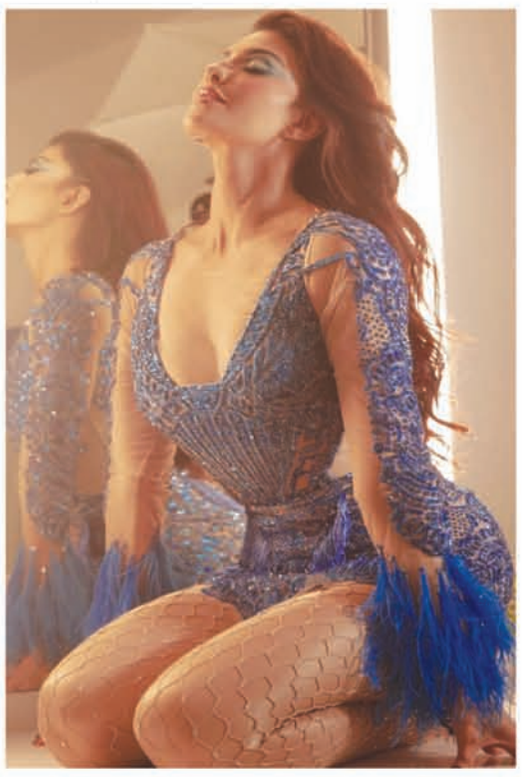

जैकलीन फर्नांडिस ने अपनी सफाई में क्या कहा ?

एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की बात करें तो उन्होंने अपनी सफाई में कहा था कि उन्हें जानबूझकर इस मामले में फंसाया गया है और उनके ऊपर लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं. एक्ट्रेस के मुताबिक सुकेश चंद्रशेखर और अदिति सिंह ने उनके साथ धोखाधड़ी की है. वे कभी भी सुकेश के साथ किसी रिलेशनशिप में नहीं रही हैं.

क्या है जैकलीन से जुड़ा पूरा मामला ?

इस मामले की बात करें तो साल 2021 में ठग सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्डरिंग का मामला सामने आया था. जांच में ये भी सामने आया था कि सुकेश के कई स्टार्स के साथ भी कनेक्शन हैं जिन्हें उसने महंगे गिफ्ट्स भी दिए थे. इसी दौरान जैकलीन फर्नांडिस समेत कुछ और स्टार्स का नाम भी सामने आया था. इसके बाद से ही जैकलीन निशाने पर हैं और उन्हें इस केस से छुटकारा नहीं मिल पाया है.

वर्क फ्रंट पर क्या कर रहीं जैकलीन ?

हालांकि इन सब चुनौतियों के बाद भी एक्ट्रेस वर्क फ्रंट पर सामंजस्य बनाने की कोशिश कर रही हैं. एक्ट्रेस की पिछली फिल्म हाउसफुल 5 थी. वहीं साल 2025 में वे अब तक रेड 2 और फतेह जैसी फिल्मों का हिस्सा बन चुकी हैं. फिलहाल वे वेल्कम टू द जंगल फिल्म का हिस्सा हैं.

22 साल पुरानी वो फिल्म, जिसमें अक्षय कुमार की जिद पर हुई करीना कपूर की एंट्री, मेकर्स को लगा करोड़ों का चूना

अक्षय कुमार सालभर फिल्में रिलीज करने के लिए जाने जाते हैं. हर साल उनकी 3-4 फिल्में आसानी से रिलीज हो ही जाती हैं. हाल ही में पूर्व सीबीएफसी प्रमुख और फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी ने अक्षय कुमार की 22 साल पुरानी एक फ्लॉप फिल्म की कास्टिंग को लेकर खुलासा किया. उन्होंने बताया की कैसे अक्षय के जोर देने पर उस फिल्म में यंग करीना कपूर को साइन किया गया था. फिल्ममेकर ने बॉलीवुड कास्टिंग को लेकर भी खुलकर बात की.पूर्व सीबीएफसी प्रमुख पहलाज निहलानी ने बॉलीवुड कास्टिंग के बदलते तौर-तरीकों और बढ़ते बजट के बारे में अपने विचार शेयर किए. यूट्यूब चैनल लर्न फ्रॉम द लीजेंड पर बात करते हुए उन्होंने 2003 की फिल्म तलाश- द हंट बिगिन्स के निर्माण के दौरान के एक पल को याद किया, जब अक्षय कुमार ने जोर देकर कहा था कि करीना कपूर को लीड रोल में लिया जाए.

अक्षय ने मेकर्स के सामने रखी थी ये शर्त

पहलाज निहलानी ने बताया कि कैसे कास्टिंग का फैसला पूरी तरह से डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के अधिकार क्षेत्र में होता था, जिसमें एक्टर्स शायद ही कभी शामिल होते थे. उन्होंने कहा, पहले, निर्माता और निर्देशक कास्टिंग करते थे और हीरो कास्टिंग में नहीं बोला करते थे. मेरे साथ कास्टिंग में इंटरफेयर करने वाले पहले एक्टर अक्षय कुमार थे और फिल्म 2002 में 'तलाश' थी. उन्होंने मुझसे कहा कि हम कल फिल्म शुरू कर सकते हैं, और आप मुझे जो भी अमाउंट देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन इस फिल्म की हीरोइन करीना कपूर होंगी.

साल की सबसे महंगी फिल्म थी 'तलाश'

फिल्ममेकर ने बताया कि यह 'तलाश' उस समय की सबसे महंगी फिल्मों में से एक थी, इसे 22 करोड़ रुपये में बनाया गया था. यह उनके करियर में पहली बार था जब किसी एक्टर ने एक फिक्स एक्ट्रेस की मांग की थी.

पहलाज निहलानी ने बताया कि अक्षय का वो फैसला इमेज को लेकर था. उन्होंने अपनी बात पूरी करते हुए बताया, कभी-कभी, जैसे-जैसे एक्टर्स बूढ़े होते जाते हैं, वे यंग एक्ट्रेसेस के साथ एक्टिंग करना चाहते हैं ताकि उनकी खुद की उम्र कम दिखे. यह पहली बार था जब मैंने ऐसा सुना, लेकिन इन दिनों एक्टर्स ही सब कुछ तय करते हैं और निर्माता कूरियर सेवा के रूप में काम करते हैं. बता दें, 'तलाश' पर फ्लॉप साबित हुई थी.

1200 करोड़ छापने वाला सुपरस्टार, जिसे आलिया भट्ट ने एक नहीं, तीन बार ठुकरा दिया!

बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट अपनी अपकमिंग फिल्मों की तैयारियों में बिजी हैं. यूं तो अपनी एक्टिंग और सफलता के चलते काफी डिमांड में हैं. पर एक्ट्रेस का पूरा फोकस इस समय आने वाली फिल्मों पर हैं. जल्द YRF स्पाई यूनिवर्स की ALPHA में दिखेंगी. जिसके लिए फैन्स भी काफी एक्साइटेड हैं. वैसे तो आलिया भट्ट ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं. इसी बीच आलिया साउथ के एक बड़े एक्टर को लेकर चर्चा में हैं. कहा जा रहा है कि उन्होंने तीन बार उनके अपोजिट ऑफर हुई फिल्म को ठुकराया दिया.आलिया भट्ट को साल 2022 में एसएस राजामौली की फिल्म में देखा गया था. RRR में एक्ट्रेस का कैमियो था, जहां वो राम चरण के साथ दिखी थीं. हालांकि, फिर ऐसे चर्चे हैं कि वो फहाद फाजिल के साथ काम करती नजर आएंगी.

आलिया ने 1200 करोड़ी एक्टर को ठुकराया ?

हाल ही में cinejosh पर एक रिपोर्ट छपी. इसके मुताबिक, आलिया भट्ट ने जूनियर NTR को एक बार नहीं, बल्कि तीन बार रिजेक्ट किया है. ऐसी चर्चा है कि एक्ट्रेस को उनके अपोजिट तीन बार काम करने का ऑफर मिला था. पर वो मना करती चली गईं. हालांकि, इसके पीछे वजह पर्सनल नहीं, प्रोफेशनल है. कभी रोल पसंद न आना, तो कभी सेकंड हीरोइन का रोल ऑफर होने पर उन्होंने न कह दिया. कहा जा रहा है कि कहानी पसंद न आने की वजह से भी एक्ट्रेस ने मना किया था.

हालांकि, जूनियर एनटीआर को तीन बार ठुकराना बड़ी बात है. जिसने सभी फैन्स को हैरान कर दिया है. लोग चाहते हैं कि आलिया भट्ट भी जल्द जूनियर एनटीआर के अपोजिट दिखे. दरअसल जूनियर एनटीआर और राम चरण काफी अच्छे दोस्त हैं. और राम चरण की आलिया से भी अच्छी बॉन्डिंग है, लेकिन देखना होगा कि यह हो पाता है या नहीं.

इन फिल्मों से धूम मचाएंगे

जूनियर एनटीआर की पिछली फिल्म 'देवरा' थी, जो कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी. अब बारी है 'वॉर 2' की, जो 14 अगस्त को रिलीज होगी. ऋतिक रोशन की फिल्म में वो विलेन बनने वाले हैं. वहीं इसके बाद प्रशांत नील के साथ एक पिक्चर में धमाल मचाते नजर आएंगे. हालांकि, आगे भी कई और डायरेक्टर्स से उनकी बातचीत चल रही है. हालांकि, देवरा से पहले ऋऋक्र में दिखे थे, जिसने दुनियाभर से 1200 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया था.

यहां दाल नहीं गलने वाली...

तेजस्वी प्रकाश

संग रिश्ते को 'नकली' कहने वालों पर भड़के करण कुंद्रा

टीवी के पॉपुलर एक्टर करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश का रिश्ता साल 2021 से लगातार सुर्खियों में है. 4 साल पहले 'बिग बॉस 15' के घर में शुरू हुई इनकी लव स्टोरी घर के बाहर भी टिकी हुई है और फैंस इन्हें प्यार से 'तेजरन' कहकर बुलाते हैं. लेकिन हाल ही में कुछ सोशल मीडिया हैंडल और यूट्यूब चैनलों ने उनके रिश्ते को 'फर्जी' बताकर करण पर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड अनुषा दांडेकर को धोखा देने का आरोप लगाया. अक्सर इस तरह की खबरों को इग्नोर करने वाले करण कुंद्रा ने इस बार उनकी निजी जिंदगी को लेकर गलत खबरें फैलाने वालों की जमकर क्लास लगाई है.

करण कुंद्रा ने बुधवार को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर कई यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया हैंडल के थंबनेल के स्क्रीनशॉट शेयर किए. इन थंबनेल में तेजस्वी प्रकाश के साथ उनके रिश्ते को 'फेक और नकली दिखाया जा रहा था और साथ ही इनमें से कुछ वीडियो में करण कुंद्रा पर ये आरोप भी लगाए गए थे कि उन्होंने अतीत में बिग बॉस में अपने एक को-स्टार को गाली दी थी और थप्पड़ भी मारा था. इन ट्रोल्स को करारा जवाब देते हुए करण ने लिखा, 'थोड़ा और पैसा लगाओ तुम लोगज्यहां तो दाल गल नहीं रही है तुम्हारी.'

गॉसिप फैलाने वालों पर फूटा करण का गुस्सा

करण ने एक्स (पहले ट्विटर) पर अपने कई फैंस को जवाब देते हुए ये भी साफ किया कि उनके बारे में गलत खबरें फैलाने वाले कोई मीडिया न्यूज पेज या चैनल नहीं हैं, बल्कि सिर्फ पैसे के लिए झूठी खबरें लोगों में फैलाने वाले गॉसिप मॉन्गर्स हैं. उन्होंने लिखा, 'करेक्शन .. ये कोई मीडिया पेज नहीं हैंज्ये पेज पैसे के लिए ऐसा करते रहते हैं.' उन्होंने आगे कहा, 'दरअसल मैं इन लोगों के लिए एक गो-फंड-मी शुरू करने के बारे में सोच रहा हूं, क्योंकि ये सभी बेचारे बहुत कम बजट वाले पेजों को ही इस तरह की खबरें फैलाने के लिए पे (भुगतान) कर रहे हैं.. बहुत ही दुखद है'

शादी की झूठी खबरों पर भी तोड़ी थी चुप्पी

ये पहली बार नहीं है जब सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले करण ने अपने रिश्ते को लेकर उड़ रही अफवाहों पर बात की हो. 3 महीने पहले अप्रैल में करण ने उनके और तेजस्वी के नेटफ्लिक्स के 'दुबई ब्लिंग' के आने वाले सीजन में शादी करने की खबर का खंडन किया था. उन्होंने कहा था कि 'मैं अब इन बातों से तंग आ गया हूं', मैं सभी टैबलॉयड से कहना चाहता हूं कि आप इस साल या फिर अगले साल मेरी शादी करवा देंगे, फिर आप में से कुछ लोग एक रियलिटी शो में मेरी सगाई का ऐलान भी कर देंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम इस समय दुबई में हैं. मैं ये भी समझता हूं कि इस तरह की खबरों से आपको बहुत सारे नंबर मिल जाते हैं.

न्यूज फ्लैश

आईटीबी इंडिया 2025 ने नई थीम 'अनुभव का व्यवसाय' लॉन्च किया

दिव्य दिल्ली : आईटीबी इंडिया की ओर से आगमी 2 से 4 सितंबर 2025 तक मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में अपने चौथे संस्करण के लिए नई थीम "अनुभव का व्यवसायः लक्षित विकास के लिए क्यूरेटेड यात्रा" को लॉन्च किया गया। माइस शो इंडिया और ट्रैवल टेक इंडिया के साथ संयुक्त रूप से आयोजित यह कार्यक्रम भारतीय और दक्षिण एशियाई बाजारों के लिए अनुकूलित व्यक्तिगत, अनुभव-संचालित यात्रा के समाधानों पर प्रकाश डालने वाला एक शक्तिशाली बी2बी प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। थीम लॉन्च नई दिल्ली के ली मेरिडियन होटल में मंगलवार को बेहद भव्य एवं आलीशान तरीके से किया गया। इस आयोजन में 400 से अधिक प्रदर्शकों, 600 से अधिक योग्य खरीदारों और 8,000 से अधिक उपस्थित लोगों के साथ, आईटीबी इंडिया 2025 वेलनेस एस्केप और सिनेमाई यात्राओं से लेकर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अन्वेषण तक विशिष्ट यात्रा का अनुभव प्रस्तुत किया जायेगा। इसमें शामिल होने वाले प्रमुख प्रतिभागियों में भारत, इटली, जापान, मलेशिया (सरवाक), केन्या और श्रीलंका जैसे देशों के पर्यटन बोर्ड, प्रमुख होटल, डीएमसी, एयरलाइंस और ट्रैवल टेक प्रदाता शामिल होंगे।इस मौके पर मेसे बर्लिन एशिया पैसिफि क के कार्यकारी निदेशक डैरेन सीह ने कहा, भारत और दक्षिण एशिया के अनुभव की प्रथम यात्रा बाजारों के रूप में विकसित हो रहे हैं। "आईटीबी इंडिया 2025" इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अत्याधुनिक और रणनीतिक साझेदारी के लिए उत्प्रेरक साबित होगा।आईटीबी इंडिया 2025 में कई बेहतरीन विशेषताओं पर प्रकाश डाला जाएगा, जिन्हें क्यूरेटेड यात्रा के रुप में अपने विषय को जीवंत बनाने के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। इसमें अनुभव के मुताबिक इमर्सिव शोकेस पेश किया जायेगा। यहां उपस्थित लोग स्थानीय व्यंजनों का भी स्वाद ले सकेंगे। यहां स्वास्थ्य उपचारों का पता लगा सकेंगे और इसके साथ आभासी वास्तविकता के माध्यम से गंतव्यों का अनुभव कर सकेंगे।

राजा वीरभद्र सिंह को किया याद

दिव्य दिल्ली-अमरप्रीत सिंह (सोलन)

सोलन के कांग्रेस कार्यकताओं ने स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह की पांचवी पुण्यतिथि पर सोलन के नागरिक अस्पताल मे मरीजों को फल और जूस देकर उन्हें याद किया ज़िला युवा कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष अमित ठाकुर ने कहा कि स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह आज शारीरिक तौर पर हमारे बीच मौजूद नहीं है लेकिन वे आज भी प्रत्येक हिमाचल के दिलों में जीवित है जिस प्रकार कोई भी दुखियारा जब राजा साहब के पास अपने दुख को व्यक्त करता तो उस व्यक्ति के साथ साथ राजा साहब भी भावुक हो जाते थे और अपने सम्पूर्ण जीवन में गरीब, दुखी और असहाय लोगों की मदद के लिए हर संभव प्रयास करते थे इस मौके पर उनके साथ यूंका ज़िला अध्यक्ष सचिन कश्यप, जय प्रकाश सोलन विधानसभा अध्यक्ष सुशील कोडंल पूर्व अध्यक्ष अंकुर ठाकुर संधीरा सिंह उपाध्यक्ष जिला महिला कांग्रेस , कुसुम शर्मा, सीता ठाकुर पूर्व प्रधान बिशा सुभद्रा रचईक ज़िला महासचिव महिला कांग्रेस , विकास ठाकुर आदि लोग उपस्थित रहे

जिला प्रशासन द्वारा मेरे सिंचाई विभाग के साथ चल रहे मामले को मंदिर के साथ जोड़ना गलत

दिव्य दिल्ली : रंधावा (पठानकोट)

ज़िला पठानकोट प्रशासन की ओर से सुजानपुर के पुल नंबर पांच के निकट मंदिर तोड़ने के मामले में उस वक्त नया मोड़ सामने आ गया जब प्रशासन द्वारा जिस मंदिर तोड़ने के लिए जिस व्यक्ति के मामले को आधार बनाकर कारवाई की जा रही थी ने प्रैस वार्ता का आयोजन कर प्रशासन पर माननीय हार्डकोर्ट के चीफ जस्टिस आधारित दो जजों की बेंच के फैसले को गलत तरीके से लोगों के सामने पेश करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्रकारों को संबोधित करते हुए भारत भूषण पुत्र राज कुमार निवासी पठानकोट ने बताया कि माधोपुर नहर किनारे किसी व्यक्ति द्वारा सिंचाई विभाग की जमीन पर निर्माण कार्य किया जा रहा था। जिसको लेकर मेरी ओर से 6 दिसंबर को सिंचाई विभाग को एक आरटीआई डालकर जानकारी मांगी थी थी साथ ही इस मामले संबंधी सिंचाई विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेट्री कृष्ण कुमार को भी शिकायत की गई थी। जब विभाग की ओर से इस मामले संबंधी कोई कारवाई नहीं की गई तो मैने अपने वकील के माध्यम से 4 फरवरी 2025 को सिंचाई विभाग, एक्साइज एंड टेक्सटेशन विभाग, एडीजीपी विजिलेंस पंजाब और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पार्टी बनाते हुए माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में केस दायर किया था। इस मामले में माननीय हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमित गोयल आधारित दो जजों की बेंच ने सिंचाई विभाग को उक्त विभाग की सरकारी जमीन से कब्जे हटाने को कहा था। हार्डकोर्ट के आदेश में कहीं भी धार्मिक स्थल को हटाने का आदेश नहीं दिया गया है।

भाजपा सोलन से मंडी के बाढ़ पीड़ितों को राहत, भेजी कंबल और रसोई किट

दिव्य दिल्ली : अमर पुंज (सोलन)

हिमाचल प्रदेश में जारी बारिश और बाढ़ के प्रकोप के बीच सोलन जिले से एक संवेदनशील और सहायक पहल की गई है। बुधवार 9 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी सोलन शहरी मंडल ने मंडी जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत सामग्री रवाना की।

यह सामग्री PWD रेस्ट हाउस सोलन से रवाना की गई, जिसमें 37 रसोई किट और 650 कंबल शामिल थे।

कुल्लू कोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी

दिव्य दिल्ली : (कुल्लू)

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला सत्र न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जिसके बाद कुल्लू पुलिस की टीम की मौके पर पहुंच गई है और एहतियात के तौर पर कोर्ट परिसर को खाली करवा दिया गया है। तो वही बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड भी मौके पर तैनात है। मेल के माध्यम से मिली धमकी के बाद पूरे कोर्ट परिसर को खाली करवाया गया है। सभी कर्मचारी व अधिवक्ता कोर्ट परिसर के बाहर आ गए है। इससे पहले भी उपायुक्त कार्यालय कुल्लू को मेल के जरिए बम से धमाके करवाने की धमकी मिली थी। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष तेजा ठाकुर ने कहा सूचना मिलते ही एहतियात के तौर पर कोर्ट परिसर को खाली करवाया गया है। उन्होंने कहा कि सभी से सतर्क रहने की अपील की गई है।

किसान सभा सहित अनेक श्रमिक मंडलों ने हल्ला बोल करके किया नाहन में धरना प्रदर्शन

दिव्य दिल्ली : (सिरमौर जिला)

सीटू के आवाहन पर विभिन्न श्रमिक संगठनों। हिमाचल किसान सभा ,मिड डे मिल वर्कर्स आदि ने अपनी अनेक मांगों को लेकर सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में रैली निकालकर प्रदर्शन किया। यह रैली कच्चा टैंक बस स्टैंड से आरम्भ हुई और नारेबाजी करते हुए उपायुक्त सिरमौर कार्यालय पहुंची और अपना मांगों का ज्ञापन उन्हें सौंपा। इस रैली में जिला से विभिन्न श्रमिक संगठन ,आंगनबाड़ी वर्कर्सयूनियन भी शामिल रहे। इनकी मांग हैकि श्रमिकों के लिए बनाये जा रहे श्रमिक संहिता को तुरंत निरस्त किया जाये क्योंकि ये मजदूर विरोधी हैं ,आंगनबाड़ी ,मीड डे मील वर्कर्स ,आशा कार्यक्रताओं को नियमित किया जाये और उनका मानदेय भी बढ़ाया जाये ,इसके इलावा किसानो को वन भूमि पर 5 बीघा भूमि प्रदान की जाये सीटू के महासचिव आशीष कुमार ने बतायाकि केंद्र की सरकार श्रमिकों के विरुद्ध कानून लायी है जिसे नहीं माना जायेगा इससे मजदूरों के हित प्रभावित होते हैं। इसके इलावा आंगनबाड़ी ,आशा ,मिड डे मिल कार्यकताओं के मानदेय सम्मानजनक किये जाएँ ०इन्हे नियमित किया जाये और किसानो को वन भूमि में भूमि प्रदान की जाये।

ढालपुर में बीएसएनएल कर्मचारियों ने की हड़ताल

दिव्य दिल्ली : (कुल्लू)

देशभर में बुधवार को केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल रखी गई है। तो वही हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला के मुख्यालय ढालपुर में भी बीएसएनएल के कर्मचारियों के द्वारा एक दिवसीय हड़ताल का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्र सरकार से मांग रखी गई कि जो भी कर्मचारियों की मांगे लंबित है। उन्हें जल्द पूरा किया जाए। हड़ताल को संबोधित करते हुए बीएसएनल एम्पलाइज यूनियन के परिमंडल सचिव ताराचंद ने बताया कि कर्मचारियों का वेतन साल 2017 के बाद संशोधित नहीं हो पाया है। ऐसे में बीएसएनएल की ग्राहक सेवा भी दिन प्रतिदिन गुणवत्ताहीन होती जा रही है और लोग भी बीएसएनएल की सेवाओं से मुंह मोड़ रहे हैं। ताराचंद का कहना है कि केंद्र सरकार का तर्क है कि बीएसएनएल आज घाटे में चल रहा है। लेकिन उसके लिए केंद्र सरकार तथा उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा गलत नीतियों को लाया गया और आज उसका परिणाम लाखों कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है।

चीफ इंजीनियर कार्यालय के बाहर विस्थापित परिवारों ने किया 99वें दिन भी विशाल प्रदर्शन

दिव्य दिल्ली : रंधावा (पठानकोट)

बैराज बांध विस्थापित परिवारों ने अपने रोजगार की मांग को लेकर 99वें दिन भी अपनी भूख हडताल व रोष प्रदर्शन जारी रखा। यह रोष प्रदर्शन व भूख हडताल बैराज बांध औसती कमेटी शाहपुर कंडी के पदाधिकारी व कर्मचारी नेता जसवंत संधू की देखरेख में , डैमज प्रशासन के चीफ इंजीनियर कार्यालय के बाहर किया गया, जिसमें आज मुरीद दीन मैरा, नेक अलि मैरा, भुट्टो मैरा, शरीफ दीन मैरा व शाहुया मैरा ने अपनी भूख हडताल जारी रखी। रोष प्रदर्शन कर रहे विस्थापित परिवारों में से जिनमें कामरेड जसवंत संधू, सुरजीत सिंह, रविंद्र बाबा, रोहित कुमार , हनी कुमार अदियाल, आदर्श वाला, सुनीता देवी, विनोद कुमारी, बीतू देवी, कमलेश कौर, सुनेयना शाहपुर कंडी, रजनी देवी , यशोदरा देवी, संजीब कुमार शाहपुर कंडी, राहुल शर्मा, सुनील कुमार, अंशू शर्मा, राम मजीरा, कुलदीप शर्मा, धर्मपाल , हरनाम सिंह , महिंद्र सिंह काहलों, संजय अनोत्रा, रजत बलोतरा, नरेश कुमार शर्मा, पूर्व सरपंच रमेश कुमार व अन्य कई प्रभावित परिवार शामिल हुए। रोष प्रदर्शन कर रहे विस्थापित परिवारों ने कहा कि एक तरफ पंजाब सरकार घर घर रोजगार देने के दावे व वादे कर रही है,वहीं पर प्रभावित हुए परिवारों की कोई सुध नहीं ली जा रही है।

जवाली में बैठे बीडीओ और स्टाफ, मंत्री के निर्देशों की चर्चा तेज

दिव्य दिल्ली : प्रेम स्वरूप शर्मा (नगरोटा सूरियां)

लोकतंत्र में न्यायपालिका सर्वोच्च होती है और उसके आदेशों का पालन करना हर संस्थान की संवैधानिक जिम्मेदारी है। माननीय हाईकोर्ट के 8 जुलाई के आदेश के मुताबिक हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत नगरोटा सूरियां पंचायत समिति का पुनसीर्मांकन 30 मई 2025 को प्रकाशित हो चुका था। डीलिमिटेशन हो जाने के उपरांत पंचायत समिति की सीमाओं से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती थी । समिति का पुनः सीमांकन होने के पश्चात विकास समिति फतेहपुर की 14 पंचायतों को नगरोटा सूरियां पंचायत समिति में शामिल करना विधि सम्मत नहीं था। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय ने विभाग की जून 10 ,2025 की विभागीय अधिसूचना के कार्यान्वयन पर अगस्त के पहले माह तक पूर्ण रोक लगाई है ।जिसमें पुनः सीमांकन को विधि सम्मत नहीं माना है ।इसी अधिसूचना के अंतर्गत विकासखंड नगरोटा सूरियां का मुख्यालय भी जवाली स्थानांतरित किया गया था माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से अधिसूचना पर पूर्ण रोक लग गई है अतः अधिकारियों को किसी भी राजनीतिक दबाव में ना आकर माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार आचरण किया जाना चाहिए था अधिकारियों के इस तरह के आचरण पर क्षेत्र में चचाएँ गर्म है की यह अधिकारी न्यायालय के आदेशों को भी धता दिखाने से परहेज नहीं करते तो आम जनता की क्या सुनेंगे।

देश के संसाधनों को बेच रही केंद्र सरकार

दिव्य दिल्ली : (कुल्लू)

जिला मुख्यालय कुल्लू में ट्रेड यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर 10 से ज्यादा यूनियनों के नेताओं और पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस मौके पर सबसे पहले सीटू कार्यालय सरवरी से लेकर एक विशाल रैली निकाली गई जो उपायुक्त कार्यालय परिसर में धरने में बदल गई। यहां यूनियन के नेताओं ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को संबोधित किया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए प्रदेश सचिव सीटू प्रेम गौतम ने बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा श्रम कानून को खत्म किया जा रहा है और चार श्रम कानून लागू किया जा रहे हैं। जिस कारण देश के 57 करोड़ मजदूर प्रभावित होंगे। इन चार श्रम कानून के लागू होने से मजदूर अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा पाएगा और उसे 8 घंटे की बजाय 12 घंटे ड्यूटी करनी होगी। इसके अलावा महिलाओं को रात के समय भी कार्य करना होगा और उन्हें उचित मजदूरी भी नहीं मिल पाएगी। प्रेम गौतम ने बताया कि इसके अलावा भारत में जितने भी संसाधन है। उनका निजीकरण किया जा रहा है और मात्र कुछ लोगों को ही इसका फायदा दिया जा रहा है। ऐसे में सीटू के द्वारा इन सभी मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया और केंद्र सरकार से मांग रखी गई है कि वे निजीकरण को रोके और मजदूरों के हित में फैसला ले।

भाजपा विधायक नूरपुर रणवीर व जिला परिषद सदस्य राहुल जिले में पहुंचे

विनय महाजन (नूरपुर)

भाजपा विधायक रणवीर सिंह निक्का ने नूरपुर बीजेपी कार्यकताओं के साथ जिला मंडी में हुए आपदा प्रकरण को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया ' इनके साथ जिला परिषद सदस्य राहुल पठानिया पुत्र रणजीत सिंह पठानिया अधिवक्ता ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का दौरा करने के बाद इस मामले में गंभीरता से बातचीत की ' इस घटना को प्राकृतिक आपदा बताते हुए उन्होंने कहा कि इस संकट की घड़ी में हम आपके साथ हैं ऐसा उन्होंने अपने भाजपा शीर्ष नेता को आश्वासन दिया कि जो भी हमारे लायक सेवा होगी हम उसे जनहित मे धरातल पर करेंगे।

जन संगठनों के मजदूरों और कर्मचारियों ने की एक दिवसीय हड़ताल कर मार्केट शेड के नीचे रैली

दिव्य दिल्ली : रंधावा (पठानकोट)

देश की केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की सलाह पर आज सीटू, एटक, सीटीयू और इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन्स के अंतर्गत काम करने वाले जन संगठनों के मजदूरों और कर्मचारियों ने एक दिवसीय हड़ताल की और लेबर शेड पठानकोट के पास मार्केट शेड के नीचे रैली की, जिसकी अध्यक्षता मास्टर सुभाष शर्मा, अविनाश सैनी, अमरीक सिंह और गोपाल भगवानपुर और दविंदर मल्होत्रा ने की। रैली को विभिन्न वक्ताओं ने संबोधित किया और केंद्र सरकार और पंजाब सरकार की कॉर्पोरेट घरानों के पक्ष में आर्थिक नीतियों की निंदा की और मांग की कि चार श्रम संहिताओं को निरस्त किया जाए, न्यूनतम वेतन 100 रुपये प्रति माह किया जाए। 26,000/- प्रति माह, 12 घंटे कार्य दिवस की अधिसूचना रद्द की जाए, पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए, बिजली संशोधन विधेयक 2022 वापस लिया जाए, ठेकेदार आउटसोर्सिंग प्रणाली बंद की जाए, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, निर्माण मजदूरों और घरेलू कामगारों को सामाजिक सुरक्षा दी जाए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रद्द की जाए, छठे वेतन आयोग की शेष त्रुटियों को दूर किया जाए और कॉर्पोरेट घरानों पर लगाए गए टैक्स में वृद्धि की जाए और सुपर अमीरों पर टैक्स लगाया जाए। हड़ताल को संयुक्त किसान मोर्चा ने भी समर्थन दिया।

आत्म प्रज्ञा आश्रम बागनी में चौथे दिन की कथा में वेदों का ज्ञान दिया गया

दिव्य दिल्ली : विनय महाजन (नूरपुर)

नूरपुर आत्म प्रज्ञा आश्रम बागनी में चौथे दिन आज स्वामी वेद प्रकाश सरस्वती ने कर्तव्य कर्मों पर प्रकाश डाला' उन्होंने बताया कि हमारी पांच माताएं हैं और पांचो माता की सेवा करना हमारा परम धर्म है' पहले माता हमारी जननी माता है उसके प्रति हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनकी भरपूर सेवा सुश्रुषा करें' दूसरी हमारी गौ माता है जिसका हम दूध पीते हैं उसकी हमें सेवा और पालना करनी चाहिए ' तीसरी हमारी धरती माता है इसका हमें पोषण करना चाहिए ' वृक्षारोपण आदि करके प्रकृति का संतुलन बनाना चाहिए' चौथी माता हमारे वेद माता है ' इसका ज्ञान प्राप्त करने से सृष्टि का पालन पोषण होता है' सृष्टि के ज्ञान को प्राप्त करके स्वयं जीने की कला सीखते है और फिर दूसरों को ज्ञान प्राप्त कराए ' इससे हमारे वेद की रक्षा होती है और इससे सृष्टि का संतुलन बनता है मानवता बढ़ती है आपस में प्रेम बढ़ता है ' पांचवी माता हमारी भारत माता है जिसको हम राष्ट्र कहते हैं' राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य बनता है की हम उसकी रक्षा में हमेसा ततपर राहें जिससे हमारी संस्कृति और सभ्यता की रक्षा हो जिससे मानवता की वृद्धि हो सके और आपस में प्रेम से जीवन यापन कर सकें' आज के वेद मंत्र में आया कि मनुष्य जरावस्था से पूर्व ही मृत्यु का ग्रास बनता है इसका कारण है प्रबंधन की कमी या बोध (ज्ञान) की कमी जीवन में अगरबोध होता है तो उसका खानपान उसका रहन-सहन उसकी दिनचर्या उसकी ऋतुचार्य उसकी सारी जीवन की व्यवस्था बोध पर निर्भर होती है

न्यायाधीश ने जेल का निरीक्षण कर कैदियों का हालचाल जाना

दिव्य दिल्ली : रंधावा (पठानकोट)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश जतिंदर पाल सिंह खुरमी ने सब-जेल पठानकोट का निरीक्षण किया और कैदियों का हालचाल जाना। इस अवसर पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रूपिंदर सिंह, जेल अधीक्षक हिमांशु गोयल भी उपस्थित थे। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जेल में बने खाने का भी स्वाद चखा और उसका निरीक्षण किया। जिन कैदियों के पास वकील नहीं थे, उन्हें मुफ्त कानूनी सहायता भी दी गई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जतिंदर पाल खुरमी ने जेल में बंद कैदियों से कहा कि हर कैदी, हर बंदी को मुफ्त कानूनी सेवाओं का अधिकार है, जिसके तहत उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पठानकोट द्वारा मुफ्त वकील मुहैया कराया जाता है और कागजी कार्रवाई का खर्च भी प्राधिकरण द्वारा वहन किया जाता है।

Published, printed and owned by Rajesh.Chauhan, printed at B B Graphic printer Z--57 Okhla Industrial Area ph.2 New Delhi -110020 and published at BG 6 305 B Paschim Vihar New Delhi --110063 Editor Rajesh.Chauhan. E mail ID-rajeshchauhan4569@gmail.com, Contact No. - 9873104569, RNI No DELENG/2013/54397